WWW.Kanchanujala.in   हिन्दी दैनिक   kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

दो महीने बाद आलिया भट्ट ने खोला कॉमेंट सेक्शन

लखनऊ से प्रकाशित   सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 239   लखनऊ, बुधवार, 19 अगस्त, 2020   पृष्ठ- 6   मूल्य - 1 रुपये

देश में कोरोना के तीन करोड़ से अधिक नमूनों की जांच

19 लाख से अधिक मरीज ठीक

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में अब तक कोरोना के तीन करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और पिछले 24 घंटों में आठ लाख 99 हजार 864 नमूनों की जांच की गई है। देशभर में अब तक 19 लाख से अधिक मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं ,जो संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 2.93 गुना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को देश में कोरोना की स्थिति को लेकर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना के कुल जितने मामले सामने आए हैं, उसके मात्र 25 प्रतिशत मामले ही सक्रिय हैं, जिनका उपचार अस्पतालों अथवा होम आइसोलेशन में हो रहा है। इस समय देश में प्रतिदिन औसतन 55 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं और कोरोना मृत्यु दर भी घटकर दो प्रतिशत से नीचे रह गई है। उन्होंने बताया कि देश में एक से सात जुलाई तक औसतन प्रतिदिन 2,30,751 कोरोना जांच की गई थी और 22 से 28 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 4,21,940 नमूने प्रतिदिन और 12 अगस्त से 18 अगस्त तक यह आंकड़ा बढ़कर 8,08,488 हो चुका है। कल सबसे अधिक 899,864 नमूनों की जांच की गई थी जो एक दिन का सर्वाधिक नमूना जांच का रिकार्ड है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना की प्रतिदिन औसतन पोजिटिविटी दर घट रही है और यह दर आठ से 14 जुलाई के बीच 10.03 प्रतिशत और 22 से 28 जुलाई के बीच 9.03 प्रतिशत थी। केन्द्र और राज्य सरकारों के बेहतर क्लीनिकल प्रबंधन की वजह से यह 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच घटकर 7.72 प्रतिशत रह गयी है। देश में अब तक कोरोना के कुल 19,77,779 मरीज ठीक हो गए हैं और इस समय सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 6,73,166 है । इस समय कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 73 प्रतिशत हो गई है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सात अप्रैल को देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर केवल 7.35 प्रतिशत थी जो पांच मई को बढ़कर 27.41 प्रतिशत और नौ जून को बढ़कर 48.47 प्रतिशत हो गई थी।

पब्लिक प्लेटफार्म पर सभी को अपनी राय रखने का अधिकार

नयी दिल्ली, एजेंसी। 18 अगस्त (वार्ता) कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक प्लेटफार्म पर हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है। श्री प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक प्रश्न पर कहा कि हर भारतीय को पब्लिक प्लेटफार्म पर अपनी बात रखने का अधिकार है । उन्होंने कहा कुछ लोग इस प्लेटफार्म पर अपना एकाधिकार चाहते हैं जबकि उनका आधार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एक पब्लिक प्लेटफार्म से भारतीय जनता पार्टी के 700 पेज हटाये गये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यह समझते हैं कि जो लोग उनके अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दबाव में हैं । उन्होंने हेट स्पीच की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार कहा था इस बार आर पार की लड़ाई है ।

बारामूला मुठभेड़ में मारा गया तीसरा आतंकी, चार सुरक्षाकर्मी भी शहीद

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के क्रिरी पाटन में सुरक्षाबलों ने मंगलवार तड़के दोबारा घेराबंदी और तलाश अभियान चलाया जिसके बाद मुठभेड़ फिर शुरू हो गयी। इस मुठभेड़ में अब तक तीन आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। मारे गए तीन आतंकवादियों में से 2 लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर और उस्मान हैं। हैदर हाल में बांदीपोरा में हुई हत्याओं का मुख्य साजिशकर्ता है। वह पुलिस, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमलों में शामिल था। इसके अलावा युवाओं को आंतकी संगठनों में भी भर्ती करता था। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाबल के जवान जब एक निश्चित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे तभी वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन गोलियां चलाईं। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की जिसके साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने अंधेरे के कारण सोमवार रात अपना अभियान रोक दिया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करने के साथ ही राष्ट्रीय राइफल्स के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया। बारामूला जिले में सोमवार तड़के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और पुलिस के नाका पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ की 119 बटालियन के कांस्टेबल लोकेश शर्मा और कांस्टेबल खुर्शीद खान शहीद हो गए। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) मुजफ्फर अली डार ने भी कर्त्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

यूजीसी परीक्षा अधिसूचना मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को फैसला सुरक्षित हो गया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों के वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को तीन दिन के भीतर अपना लिखित पक्ष उसके समक्ष पेश करने का आदेश भी दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक यश दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान पेश हुए, जबकि विश्वविद्यालय अनुदार आयोग (यूजीसी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं में शिवसेना की युवा इकाई 'युवा सेना' भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितम्बर तक आयोजित कराने की यूजीसी की अधिसूचना को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि देश में कोरोना महामारी का रूप ले चुका है और हाल के दिनों में यह संख्या 27 लाख के पार पहुंच चुकी है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद एमएलए रीतलाल यादव को हाईकोर्ट ने दी राहत

पटना, एजेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय की पीठ ने एमएलसी रीतलाल यादव की याचिका पर पहले ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में अदालत ने अपना आदेश मंगलवार को दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा सात वर्षों की होती है, जबकि रीतलाल यादव मामले सात वर्ष से अधिक समय जेल में रह चुके हैं।

मोदी ने कीटाणुजनित रोगों से बचाव के लिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की

नयी दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसात के मौसम के बाद जल और कीटाणुजनित बीमारियों के होने वाले प्रकोप के प्रति मंगलवार को लोगों को आगाह करते हुए इनसे बचाव के लिए ऐहतियात बरतने की सलाह दी है। श्री मोदी ने आज दूरदर्शन के एक समाचार पर ट्वीट करते हुए लिखा, यह उष्णकटिबंधीय और रोगवाहक जनित बीमारियों का मौसम है। मैं आप सभी से उचित सतर्कता बरतने की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा, सरकार भी हालात पर नजदीक नजर रखे हुए है और प्रभावितों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। सुरक्षित रहो,खुश रहिये। प्रधानमंत्री ने वास्तव में दूरदर्शन के एक समाचार को रीट्वीट किया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि मॉनसून से मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। खबर में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दे गई है।

गौरतलब है कि बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के तेजी से फैलने का खतरा अधिक रहता है और लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है।

जन समस्याओं का निदान समय से और गुणवत्तापूर्ण होः स्मृति ईरानी

अमेठी, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि जनता की समस्याओं का निदान समय से और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और ईमानदारी से यह प्रयास हो कि विकास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। स्मृति ईरानी ई-चौपाल के द्वितीय चरण को प्रारंभ करते हुए लोगों की समस्याएं सुन रहीं थीं। स्मृति ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही सांसद ने विकासखंड भेटुआ अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खंडहर, विकासखंड संग्रामपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय करनाईपुर तथा विकासखंड भादर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भादर में ऑनलाइन संवाद कर जन समस्याएं सुनीं तथा उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

भगवान राम सभी के हैः अखिलेश यादव

इटावा, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान राम सभी के हैं, वे केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, भगवान कृष्ण सभी के हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जो सभी के हैं। उन्होंने आगे कहा, हम सभी नवरात्रि उत्सव के दौरान देवियों की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या ये देवियां भी भाजपा की हैं?ष्समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई।उन्होंने कहा, भाजपा केवल भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की सबसे कम परवाह कर रही है।

बिहार में दलित वोट बैंक पर नेताओं की नजर

पटना, एजेंसी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जहां एक तरफ एलजेपी उसे आंख दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्याम रजक तो उसे अलविदा कह चुके हैं. इन दोनों के तल्ख तेवर से ना सिर्फ एनडीए बिखर रही है. बल्कि जेडीयू का सियासी समीकरण भी बिगड़ रहा है. इसकी वजह दलित वोट बैंक है. जी हां बिहार में दलित चेहरा माने जाने वाले श्याम रजक ने सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है. वहीं एलजेपी भी बाहर जाने के लिए तैयार बैठी है. इस भगदड़ से उसका दलित वोटबैंक भी खिसक सकता है. यही कारण है कि अब रजक की विदाई से होने वाले नुकसान की भरपाई जीतनराम मांझी के जरिए करना चाहती है. पार्टी की कोशिश है कि मांझी को एनडीए में शामिल किया जाए. इसके संकेत उन्होंने खुद दिए है. मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं तो श्याम रजक इतने दिनों तक उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी के रूप में कैसे काम करते रहे. चुनाव के समय जब वो आरजेडी में चले गए हैं और जेडीयू ने उन्हें मंत्रिमंडल और पार्टी से निकाल दिया है तब वे इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसे सही नहीं कहा जा सकता है. मांझी ने कहा कि श्याम रजक मंत्रिमंडल में इतने दिनों तक लाभ लेने के बाद चुनाव के समय में नीतीश कुमार को दलित विरोधी कह रहें हैं, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है.जीतनराम मांझी का ये बयान साफइशारा कर रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं. दरअसल, जीतनराम मांझी की घर वापसी को लेकर जेडीयू की तरफसे पिछले कई महीनों से कवायद हो रही है. जेडीयू चाहती है कि मांझी की पार्टी हम का पूरी तरह से जेडीयू में विलय हो जाए. अब मांझी क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।

गोवा के राज्यपाल सत्य पाल मलिक का मेघालय ट्रांसफर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को सत्य पाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति में मलिक के स्थानांतरण को लेकर कहा गया, गोवा के राज्यपाल सत्य पाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के कर्तव्यों की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, ये नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि मलिक को 25 अक्टूबर, 2019 को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

अभूतपूर्वः रोहित, विनेश, रानी, मणिका और थंगावेलु की खेल रत्न के लिए सिफारिश

नयी दिल्ली, एजेंसी। भारत के सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा, स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मणिका बत्रा, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और रियो पैरालम्पिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगावेलु के नाम की देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सिफारिश की गयी है। खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय अवार्ड समिति ने खेल रत्न के लिए पहले चार नामों की सिफारिश की थीजिसमें बाद में रानी रामपाल का नाम भी जुड़ गया। इन पर अंतिम फैसला केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को लेना है। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा थे। कमेटी के सदस्यों में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह, पैरालम्पिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, पूर्व टेबल-टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता और मुक्केबाज वेंकटेशन देवराजन शामिल थे। समिति ने साई के मुख्यालय में बैठक की और इन नामों की सिफारिश की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नियमों में खेल रत्न के लिए यह नियम है कि केवल ओलम्पिक वर्ष में एक से ज्यादा खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया जा सकता है और गैर ओलम्पिक वर्षो में एक खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षो से यह परंपरा चल रही है कि एक से ज्यादा खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया जा रहा है। हालांकि यह पहला मौका है जब पांच खिलाड़ियों के नाम की खेल रत्न के लिए सिफारिश की गयी है। इससे पहले 2016 के रियो ओलम्पिक के बाद चार खिलाड़ियों रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू, कांस्य विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक, चौथे स्थान पर रही जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और निशानेबाज जीतू राय को खेल रत्न सम्मान दिया गया था। 2009 में तीन खिलाड़ियों बॉक्सर एमसी मैरीकॉम, विजेंद्र सिंह और पहलवान सुशील कुमार को खेल रत्न दिया गया था। विजेंद्र और सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलम्पिक में कांस्य पदक जीते थे जबकि मैरीकॉम चौथी बार विश्व चैंपियन बन चुकी थीं। 1997 में वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को, 2003 में निशानेबाज अंजलि भागवत और एथलीट के बीनामोल को, 2012 में लंदन ओलम्पिक के बाद निशानेबाज विजय कुमार और पहलवान योगेश्वर दत्त को खेल रत्न मिला।

बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों का यूपीएससी में हो रहा चयनःनकवी

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा प्रतिभाओं के 'प्रोत्साहन, प्रमोशन एवं प्रोग्रेस' के लिए बड़े पैमाने पर किये गए पुख्ता प्रयासों का परिणाम है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की 'नई उड़ान' योजना के तहत फ्री-कोचिंग हासिल कर गरीब, कमजोर, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 22 युवा इस वर्ष देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में चयनित हुए हैं। श्री नकवी ने मंगलवार को यहां अंत्योदय भवन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'नई उड़ान' योजना का लाभ उठाकर केंद्रीय सिविल सेवा 2019 में चयनित होने वाले युवाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के नौजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर इससे पूर्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं हुई जिससे उनकी काबिलियत की कद्र हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बिना भेदभाव के प्रतिभाओं को सम्मान एवं सशक्तिकरण का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में चुने जा रहे हैं। इस वर्ष भी 145 से ज्यादा अल्पसंख्यक सिविल सेवा में चयनित हुए हैं। पिछले तीन वर्षों से इसी तरह उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। यूपीएससी में चयनित ये युवा, अल्पसंख्यक एवं कमजोर तबकों के लिए 'रोल मॉडल' हैं। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 'नई उड़ान', 'नया सवेरा' योजनाओं के तहत गरीब, कमजोर, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से यूपीएससी एवं अन्य प्रशासनिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग सेवा परीक्षाओं आदि के लिए बड़े पैमाने पर निशुल्क कोचिंग मुहैया करा रहा है।

योगी ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान करने के दिये निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आज यहां लोकभवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ राहत का कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए बजट की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जल बहाव के कटान से प्रभावित भूमि के समीप स्थित स्कूल व पंचायत भवनों में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों हेतु शरणालय न बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित जनपदों में पशुओं के चारे-भूसे की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ पशु टीकाकरण का कार्यक्रम समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। श्री राजभर ने बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित है। बाढ़ के संबंध में निरन्तर अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0 की 15 टीमें तथा एस0डी0आर0एफ0 व पी0ए0सी0 की 07 टीमें इस प्रकार कुल 22 टीमें तैनाती की गयी है। 1,176 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है। बाढ़,अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव व राहत प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। श्री राजभर ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण कराया जा रहा है। इस किट में 17 प्रकार की सामग्री जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 05 किलो लाई, 02 किलो भूना चना, 02 किलो अरहर की दाल, 500 ग्रा0 नमक, 250 ग्रा0 हल्दी, 250 ग्रा0 मिर्च, 250 ग्रा0 धनिया, 05 ली0 केरोसिन, 01 पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 01 ली0 रिफाइन्ड तेल, 100 टेबलेट क्लोरीन एवं 02 नहाने के साबुन वितरित किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि अब तक राहत सामग्री के अन्तर्गत 90,372 खाद्यान्न किट व 2,05,917 मी0 तिरपाल का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 267 मेडिकल टीम लगायी गयी है। श्री राजभर ने बताया कि बाढ की आपदा से निपटने के लिए प्रदेश में 331 बाढ़ शरणालय तथा 748 बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी है। वर्तमान में प्रदेश के 16 जनपद (अम्बेडकरनगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, गोण्डा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुरखीरी, मऊ, देवरिया, संतकबीरनगर, तथा सीतापुर) के 838 गांवों बाढ़ से प्रभावित है।

योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में

हाल में ही समारोह में शामिल हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुए पॉजिटिव

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं. इस बार प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग कोरोना की चपेट में आ गए हैं. उनकी कोविड- 19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज के जरिए जारी की है. जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट करा दिया गया है. मंत्री अतुल गर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 15 अगस्त को मेरा रैपिट टेस्ट हुआ जिसमें मैं नेगेटिव आया था पर कल रात 9 बजे रेपिट टेस्ट में पॉजिटिव आया हूँ 16 से 18 तारिक के बीच जो भी मुझसे मिले है उन्हें अपना ख्याल रखते हुए टेस्ट कराना उचित रहेगा इसमे मेरी किसी भी प्रकार की सहियोग चाहिए तो मुझे आप फोन कर सकते है या मेरे सहियोगी राजेन्द्र मित्तल, अजय राजूपत से भी फोन पर बात कर सकते है.यूपी सरकार के मंत्रियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले थम नहीं रहे है. लगातार एक के बाद एक कई मंत्री अभी तक संक्रमित हो चुके हैं.जिनमें दो मंत्रियों कमल रानी वरूण और चेतन चौहान की मौत भी हो चुकी है.वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री के संक्रमित होने से चिंता और गहरा गई है. स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कुछ ही दिनों पहले बरेली का दौरा किया था. वहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में बने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था. जिस कंट्रोल रूम की तारीफसीएम योगी ने की थी. इसके बाद उन्होने नए बने 300 बेड हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया था. वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होनें गाजियाबाद में भी अस्पताल जाकर जिले की पहली आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया था. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह तक यूपी में कोरोना के कुल 50893 मामले सक्रिय हैं. वहीं सूबे में कुल 2515 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

एसएसबी के महानिदेशक पद भार ग्रहण करते आईपीएस राकेश आस्थाना

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह भी कोरोना पॉजिटिव

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शाना सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। मंगलवार को दर्शाना सिंह की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दर्शना सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लक्षण महसूस होने पर टेस्ट कराया था। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा नेता ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर लिया है। दर्शना सिंह ने उन सभी लोगों से भी अपनी जांच कराने और सावधानी बरतने की अपील की है, जो लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं। बता दें कि इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह होम आइसोलेशन में हैं। चपेट में आकर योगी सरकार के दो मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज पीजीआई में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।

सारस्वत समारोह का आयोजन एक सितम्बर को

लखनऊ, संवाददाता। पण्डित बृजमोहन अवस्थी सुस्मृति संस्थान' एवं 'समर्पयामि फॉउंडेशन' के संयुक्त तत्वावधान में बुन्देलखण्ड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व समाजसेवी पण्डित बृजमोहन अवस्थी के जन्मदिन 1 सितम्बर के अवसर पर प्रत्येक वर्ष सारस्वत समारोह का आयोजन किया जाता है,जिसमें सांस्कृतिक,साहित्यिक व सामाजिक कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली ग्यारह विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के लिये सम्मानित विभूतियां हैं, दयानन्द पाण्डेय साहित्यकार लखनऊ, पं. बृजमोहन अवस्थी साहित्यसेवा सम्मान-2020, प्रो. पुनीत बिसरिया झांसी पण्डित महेश प्रसाद अवस्थी शिक्षाविद सम्मान-2020, डॉ संदीप अवस्थी अजमेर (राजस्थान) पं. बृजमोहन अवस्थी साहित्य-समालोचना सम्मान-2020, डॉ अनीता श्रीवास्तव लखनऊ सुमित्रा देवी अवस्थी सद्भावना सम्मान-2020, रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट, लखनऊ पण्डित हरिश्चंद्र अवस्थी विधिवेत्ता सम्मान- 2020, श्रीयुत सहावेन्द्र सिंह शशि ललितपुर पण्डित बृजमोहन अवस्थी समाज सेवा सम्मान-2020, प्रो. बहादुर सिंह परमार छतरपुर (मध्यप्रदेश) डॉ सुरेशचंद्र अवस्थी लोक संस्कृति सम्मान-2020, डॉ दुर्गाशंकर शुक्ला सर्जन, लखनऊ डॉ सतीश चन्द्र अवस्थी चिकित्सा सेवा सम्मान-2020, राखी अग्रवाल भूतपुर्व स्क्वार्डन लीडर वायु सेना पण्डित महादेव प्रसाद अवस्थी कर्तव्यनिष्ठा सम्मान-2019, अंजलि अग्रवाल चित्रकार कलाधाम नोयडा पण्डित बृजमोहन अवस्थी चित्रकला समान-2020, गीतिका वेदिका साहित्यकार टीकमगढ़(मप्र) गेंदारानी अवस्थी साहित्य सम्मान-2020, ग्यारह दिवसीय अथ किन्नर कथा संवाद के समापन दिवस पर मुख्य अतिथि महामण्डलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिने अभिनेता राजा बुन्देला, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करेंगे। विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति राकेश शर्मा ,डॉ अनिल मिश्र, देवकीनन्दन श्शांतश् उपस्थित रहेंगे। सम्मान वेबगोष्ठी के द्वारा 1 सितम्बर,20 को सायं 6 बजे से इस इि लाइव पटल पर आहूत होगा।

नागरिक सुरक्षा निदेशालय में चोरी

लखनऊ, संवाददाता। जवाहर भवन स्थित नागरिक सुरक्षा निदेशालय में कंप्यूटर के सामान तथा मोबाइल फोन सहित कतिपय अन्य चीजों की चोरी हुई है, आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर द्वारा थाना हजरतगंज को भेजे गए पत्र के अनुसार निदेशालय में कार्यरत अमित कपूर तथा जयप्रकाश के सरकारी कंप्यूटर से रैम चोरी हुआ है. इसके अलावा एक सरकारी एक्सटर्नल सीडी ड्राइव भी चोरी हुआ है, कुछ दिन पूर्व अमित कपूर का एक व्यक्तिगत मोबाइल फोन तथा मो0 शफ्कत के पास से सरकारी प्रिंटर के टोनर भी चोरी हुए थे, अमिताभ ठाकुर ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है. उन्होंने बताया कि मामले में निदेशालय के कुछ कर्मियों पर आशंका है, जो एफआईआर के बाद विवेचक को बताया जायेगा।

माया ने कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की घटनायें साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अति-दयनीय है। उन्होंने भाजपा के साथ-साथ सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंगलवार को मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि यूपी में सभी वर्गो,धर्मो व खासकर दलितों के साथ आए दिन द्वेष, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनायें साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अति-दयनीय है। इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात और बिगड़ रहे हैं, सरकार ध्यान दे। मायावती ने एक दूसरे ट्वीट में कहा

कि इन जघन्य घटनाओं को देखे तो जनता को सपा व भाजपा सरकार की कार्यशैली में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में तो यहाँ पीड़ितों की एफआइआर तक भी नहीं दर्ज की जाती थी। साथ ही उस दौरान मीडिया भी आज की तरह उतना सक्रिय नहीं था।

आपदा को अवसर में बदलने की ओर बढ़ते कदम

लखनऊ, संवाददाता। लीगल ब्लड फाउंडेशन संस्था ने कोरोना महामारी का संकट झेल रहे ग्रामीण इलाकों की ओर रुख करते हुए इस आपदा को अवसर में बदलने की शुरुआत की है। इसी क्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अभिज्ञान प्रकाश ने अपने सहयोगी संचित अग्रवाल, पुष्पेंद्र राय व अनमोल सहित सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर मंगलवार को अपनी मुहिम को काकोरी ब्लाक के तेज किशन खेड़ा व पुरैना गांव में चलाया। इस मुहिम में 400 से अधिक बच्चों को मास्क सैनिटाइजर बिस्किट व पानी की बोतल के वितरण के साथ-साथ करोना महामारी से बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक भी किया गया। लीगल ब्लड फाउंडेशन के सहयोगी संचित अग्रवाल ने बताया कि चुंकि मार्च 2020 से सभी स्कूल बंद हैं इसलिए संस्था का मूल उद्देश्य है।

भारतीय गोरखा सेवा समाज ने किया घरों पर तीज मनाने का आवाह्न

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय गोरखा सेवा समाज ने देश भर के गोरखा समाज का आवाह्न किया कि वह हरितालिका तीज पर्व 21 अगस्त को अपने अपने घरों पर मनाए। कोरोन संकट के कारण इस साल सार्वजनिक भव्य आयोजन नहीं होगा। गोरखा समाज घरों पर भगवान शंकर-पार्वती की पूजा करेगा। समाज के अध्यक्ष वेद बहादुर थापा ने कहा कि हर गोरखा को अपने समाज पर गर्व है क्यों कि उनके समाज के राम सिंह ठाकुर ने देश को कदम कदम बढ़ाए जा जैसा अमर देशभक्ति का गीत दिया है। शूटर जीतू राय और फुटबॉलर सुनील क्षेत्री ने भी समाज का नाम विश्व में ऊंचा किया है। संसद भवन में लगी 24 फिट ऊंची कांसे की स्वतंत्रा सेनानी दुर्गा मल्ल की प्रतिमा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुयी है। भारतीय संविधान सृजन समिति में अरि बहादुर गुरु और डम्बर बहादुर गुरु ने बतौर सदस्य अहम भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी के डांडी मार्च में सावित्री दीदी की भूमिका उल्लेखनीय रही। उन्होंने ने बताया कि भारतीय गोरखा सेवा समाज हर साल जनवरी में जनवरी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा, मई में ज्येष्ठ बड़े मंगल पर नए हनुमान मंदिर पर भंडारा, अगस्त सितम्बर में तीजोत्सव और दशहरा काल में दुर्गा पूजा अनुष्ठान कर समाज को जोड़ने का महती कार्य कर रहा है। स्वतंत्रा दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। 25 अगस्त को दुर्गा मल का शहीदी दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सहकारिता भर्ती घोटाले के दोषी अफ्सरों को बचाने का आरोप

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने शासन के अफ्सरों द्वारा सहकारिता विभाग में 01अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच हुई नियुक्तियीं के संबंध में एसआईटी जाँच की संस्तुतियों को दबाने के प्रयास का आरोप लगाया है,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा कि एसपी एसआईटी ने सुनील कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुभाग-3 को भेजी अपनी जाँच आख्या दिनांक 06 जनवरी 2020 में इन भर्तियों में हुई तमाम अनियमितताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया था,जाँच आख्या में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हीरालाल यादव और रविकांत सिंह ने तत्कालीन सहकारिता निबंधक शैलेश कृष्ण और अध्यक्ष रामजतन यादव के साथ मिलकर निर्धारित अर्हता को बदलते हुए अनुपयुक्त लोगों का चयन किया. साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से परीक्षा कंप्यूटर एजेंसी नियुक्त कर ओएमआर शीट में हेराफेरी की गयी. इसके अतिरिक्त राजनैतिक व्यक्तियों एवं स्वयं के रिश्तेदारों का नियमविरुद्ध ढंग से चयन किया गया,एसआईटी ने इन सभी अफ्सरों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की,नूतन के अनुसार शासन के अफ्सरों ने इस पत्रावली को पिछले 7 महीने से दबा रखा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक ओएसडी की इसमें खास भूमिका बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि एसआईटी जाँच की संस्तुति को हलका कर दोषी अफ्सरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

अज्ञात युवक का शव नहर में मिला उतराता, मचा हड़कंप

लखनऊ, संवाददाता। इटौंजा थाना क्षेत्र स्थित महोना पहाड़पुर नहर में उतराता हुआ एक अज्ञात युवक का शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। शव को उतराता देख वंहा के ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। बता दें मौके पर पहुंची पुलिस शव को नहर से बाहर निकालने के बजाए मूकदर्शक बनी रही। 2 घंटे बीतने के बाद भी शव को नहर से बाहर नहीं निकाला गया। जानकारी के मुताबिक, नहर में मिलने वाला अज्ञात शव पुरूष का बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने की काफी कोशिश की, लेकिन शव की कोई भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। बता दें मंगलवार सुबह पहाड़पुर नहर में ग्रामीणों ने एक अज्ञात का शव उतराते हुए देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उतराता शव पुरूष का बताया है।

लॉकडाउन में वरदान बना एमजॉन इण्डिया का 'आई हैव स्पेस' प्रोग्राम

लखनऊ, संवाददाता। वैश्विक महामारी कोविड19 के रोकथाम के लिए देशभर में लागू किये गये लॉकडाउन के दौरान एमजॉन इण्डिया का 'आई हैव स्पेस' प्रोग्राम तमाम ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। जिनके परिवारों की आय का साधन लॉकडाउन के दौरान बन्द या कम हो गया था। ऐसे में एमजॉन इण्डिया के 'आई हैव स्पेस' प्रोग्राम को अपनाने वालो को लाकडाउन को 15 हजार रुपये तक अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिला। जिनमें शहर में डीजे का कारोबार करने वाले आदर्श राठौड़ जैसे कई लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। जब मुझे लॉकडाउन के दौरान अपना डीजे कारोबार बंद करना पड़ा, तब इसी प्रोग्राम से मिलने वाली आय से ही मेरे परिवार का गुजारा हो सका और इसकी मदद से ही मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस जुटा सका। मैं खुश हूं कि अब मेरे पास नियमत नौकरी है। मेरे आस-पास के उपभोक्ता मुझे पहचानते हैं और जब मैं उनके पैकेज डिलीवर करता हूं।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की टेस्टिंग में वृद्धि की कार्यवाही को जारी रखने के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की टेस्टिंग में वृद्धि की कार्यवाही को निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 से 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा 40 से 45 हजार आर0टी0पी0सी0आर0 विधि से टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सम्बन्धित पोर्टल को अद्यतन रखा जाए। इसे प्रतिदिन निरन्तर अपडेट किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के

संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन घर में ही किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज तथा बस्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित करने तथा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस संचालन की कार्यवाही को और प्रभावी बनाया जाए। सभी जनपदों में ए0एल0एस0 तथा '108' एम्बुलेंस सेवाओं के 50 प्रतिशत वाहन कोविड-19 संक्रमितों के लिए उपयोग किए जाएं। प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए आवश्यकतानुसार आई0सी0यू0 बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण की भी कार्ययोजना बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों के गठन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।

विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व अधिकारियो के साथ बैठक करते विधानसभा अध्यक्ष हृदय नाराण दीक्षित

निजी स्कूलों की जोर-जबरदस्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील

लखनऊ, संवाददाता। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच निजी स्कूलों की जोर-जबरदस्ती व मनमानी के खिलाफ लखनऊ के दर्जनों वकील आज सड़क पर उतर आए हैं। तय कार्यक्रम के तहत मंगलवार दोपहर 12 बजे विधानसभा भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे वकीलों को हजरतगंज पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। भारी संख्या में तैनात लखनऊ पुलिस व पीएसी के जवानों ने वकीलों को परिवर्तन चौक चौराहा पर ही रोक लिया। जिसके बाद दर्जनों वकील सड़क पर ही बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने लगे। लखनऊ बार एसोसिएशन व लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के इस संयुक्त प्रदर्शन को खत्म कराने का मोर्चा डीसीपी पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने संभाला। भारी पुलिस जवानों साथ पहुंचे डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने पदाधिकारियों की

हर मांग शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद वकीलों ने डीसीपी को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों की फीस 40 से 50 फीस तक कम की जानी चाहिए। कोरोना संकट के चलते पिछले कई महीनों से सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। लॉकडाउन और कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित अभिभावकों से भारी-भरकम फीस वसूलना उचित नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जब अधिकतर लोगों की नौकरियां और कारोबार लगभग खत्म हो गया तब निजी स्कूलों को अभिभावकों को भी फीस में राहत देनी चाहिए।

स्वास्थ्य मेला जैसे कार्यक्रम ही लाएँगे स्वास्थ्य के प्रति सोच में बदलाव

लखनऊ, संवाददाता। कोविड 19 के अनलॉक फेज में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ब्रेकथ्रू संस्था ने आज मोहनलालगंज ब्लाक के लालपुर ग्राम पंचायत स्थित ट्रेनिंग सेन्टर में हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैम्प के माध्यम से किशोर किशोरियों को कोविड 19 के समय मे अपने स्वास्थ्य की देखभाल हेतु जानकारी भी दी गई, इस अवसर पर बीडीओ मोहनलालगंज, अजीत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से महिलाओं से जुड़ी हिंसा और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों जैसे बाल विवाह,लैंगिक भेदभाव इत्यादि पर कार्य करने वाली संस्था ब्रेकथ्रू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से उनके स्वास्थ्य के प्रति सोच में बदलाव आएगा एवं लोग अपनी बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। इस तरह के कार्यक्रम के लिए ब्रेकथ्रू के प्रयासों को धन्यवाद देता हूँ जिसने कोविड 19 के समय भी लोगो को जागरूक करने के लिए गांव में काम कर रही है। ब्रेकथ्रू एवं किशोरियों की खेल के मैदान की मांग पर उन्होंने तुरंत उस पर अपनी सहमति दी और जिम और खेल के सामान जल्द ही उपलब्ध कराएंगे एवं लड़कियां भी गांव में खेल-कूद की गतिविधियाँ आयोजित हो सकेंगी। मोहनलालगंज ब्लाक सीएचसी इंचार्ज डॉ.ज्योति कामले ने बताया कि लोगों के बीच मे कम से कम दो मीटर की दूरी जरूरी है और हाथ की साफ-सफाई के साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें।इसके अलावा उन्होंने ,माहवारी के समय शारिरिक सफाई एवं पौष्टिक खानपान का प्रयोग करने का सुझाव किशोरियों को दिया। इस कार्यक्रम में ब्रेकथ्रू की राज्य प्रमुख कृति प्रकाश ने भी हिस्सा लिया और किशोरियों की कोविड 19 के समय कैसे स्वास्थ्य उनकी शिक्षा में ड्राप आउट की समस्या को बढ़ा रहा है इस पर बातचीत की एवं किशोरियों एवं महिलाओं को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में सभी को स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया जिसमें कोरोना से बचने के लिए मास्क,साबुन,सैनिटरी नैपकिन,सैनिटाइजर,फेसशील्ड का वितरण किया गया।

बड़ी-बड़ी बातों से नहीं छोटे-छोटे कामों से देशहित में योगदान सर्वोपरिः एस.डी.एम

बेहतर समाज एवं मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर्तव्य निष्ठावान से ही संभव

प्रयागराज। देश को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बड़ी-बड़ी बातों से नहीं देश हित में छोटे-छोटे कामों से देनी होगी... उक्त बातें तहसील परिसर में 74वाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपजिलाधिकारी करछना, आकांक्षा राणा ने कही। तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, आपको उस व्यक्ति को न्याय दिलाना है, जो आप को प्रभावित नहीं कर सका, जो मुझ से नहीं मिल सका, तहसीलदार से नहीं मिल सका, उसको दिलाने के लिए न्याय आप हैं। आगे अपने संबोधन में कहा सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट मत लगाइए, रिपोर्ट लगाना काम नहीं है। आप को सही व गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाना है। स्वतंत्रता दिवस कि किसी की पूजा करके ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान गाकर या व्हाट्सएप, फेसबुक पर तिरंगा लगाकर न मनाए, इसको सही आधार पर मनाइए कि स्वतंत्रता दिवस से मैंने क्या-क्या सीख ली। अगर आप क्षेत्र में न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो एक दृष्टि लेकर जा रहे हैं, एक नया संकल्प लेकर जा रहे हैं। जो मेरे जीवन में क्या मायने हैं और मैं क्या कर सकता हूं, अपनी ताकत को पहचानिए। सिर्फ रिपोर्ट लगाने व हस्ताक्षर लगाने से नहीं है। आप उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जो असहाय व्यक्ति आप को न्याय का देवता मानते है।

अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पहचानने की आवश्यकता

उप जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि, उनके संघर्ष से हमें आजादी मिली है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर नए भारत के निर्माण के लिए शपथ लेनी चाहिए। हम स्वच्छ, गरीब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, संप्रदायवाद मुक्त एवं जातिवाद मुक्त से भारत के लिए निर्माण के लिए कार्य करें। उप जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधन करते हुए, कहा कि हम जिस पथ पर भी कार्यरत हैं, वहां रहते हुए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम जनता की समस्याओं का निवारण त्वरित व न्याय पूर्ण करें। एसडीएम आकांक्षा राणा ने इस बात पर भी बल दिया वर्तमान में सभी को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज एवं मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें।

तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, महिला घायल

बाराबंकी। तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा लोनीकटरा थाना क्षेत्र के हाइवे पर मंगलपुर चौराहे पर समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने इसी थाना क्षेत्र कर ललाई खेड़ा गांव निवासी 52 वर्षीय रामलली पत्नी देव नारायण पाल मंगलपुर चौरहे पर सामान ख़रीदने आई थी। जो बाइक की टक्कर से घायल हो गई। आस पास के लोगो ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। जहा से महिला की गंभीर हालत देख डॉक्टर ने लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया। फिर हाल बाइक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है लेकिन बाइक चालक बाइक छोड़ फरार हो गया।

प्राधिकरण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जा रहे अवैध निर्माण के सीलिंग की कार्यवाही की गई

लखनऊ। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा लखनऊ शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को दिये गये सख्त निर्देशों का अनुपालन होने लगा है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के अनुपालन में श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, डी-61, सेक्टर-पी, अलीगंज पर स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण किए जाने पर विहित प्राधिकारी द्वारा सील करने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके अनुपालन में आज दिनांक-18.08.2020 को श्री ओ0पी0 मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में क्षेत्रीय थाना पुलिस बल तथा प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से सील किया गया।

बन्दरो के आतंक से आफत में जान

प्रयागराज। लालापुर क्षेत्र के मनकामेश्वर महादेव धाम मन्दिर में इस समय बन्दरो ने आतंक मचा रखा है,कयी श्रद्धालुओं को इन बन्दरो ने काट लिया जिससे श्रद्धालु भयभीत नजर आने लगे,वही मन्दिर पुजारी कल्लू बाबा को भी नही छोड़ा इन बन्दरो ने बाबा को कयी जगह हाथ पैर मे काट कर जख्मी कर दिया,वही शनिवार को अयोध्या प्रसाद तिवारी मन्दिर के नीचे छाया में लेटे थे कि मन्दिर का खूंखार बंदर ने उनके ऊपर सीधा झपट्टा मारकर हाथ पर काट लिया,नजदीकी उपचार न होने से तत्काल सी एच सी शंकरगढ़ गये लेकिन वहाँ पर इंजेक्शन नही लगा अस्पताल के कर्मचारी ने कहा कि इंजेक्शन नही है। बन्दरो के बढ़ते आतंक से श्रद्धालु से लेकर ग्रामीण तक भयभीत रहने लगे,क्योंकि इन बंदर के साथ एक बड़ा बन्दर जो लगातार काट रहा है उसके गतिविधियों से पता चलता है कि कही ए बन्दर पागल तो नही हो रखा है।क्योंकि महिलाओं सहित दसो लोगो को काट कर जख्मी कर रखा है,और इसकी आदत बनती चली जा रही है,मन्दिर के पास इस बंदर के आतंक से किसान अपनी खेती की रखवाली करने से डरने लगे कि कही पागल बन्दर काट न ले।अगर समय रहते वन विभाग इस बन्दर को अपने कब्जे में नही कर लेता तो किसी न किसी को काटता रहेगा। इस विषय पर रेंजर शंकरगढ़ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जल्द वन विभाग की टीम मनकामेश्वर महादेव मन्दिर जायेगी और खूंखार बंदर को अपने कब्जे में जल्द लेगी।

पुण्यतिथि पर सुभाष चन्द्र बोस को किया गया नमन

प्रयागराज। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु श्रीवास्तव (अंकुर) के नेतृत्व में सिविल लाइन्स सुभाष चौराहा स्थित, सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर दर्जनों कायस्थ सदस्यों के साथ माल्यापर्ण कर उन्हें यादा करते हुए श्रद्धा सुमन अपिर्तत किया गया तथा उनके विचारों पर चलने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा प्रकोष्ठ) संजय श्री राजन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज जो देश की जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए सभी नवजवान साथियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए एवं अपने आदर्श नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को आदर्श बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव जय श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव, महामंत्री देवाशीष श्रीवास्तव, नवल किशोर श्रीवास्तव, पियुष श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, वैभव श्रीवास्तव, रिशू श्रीवास्तव, सागर श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव आदि कायस्थ साथी मौजूद रहें। इसी क्रम में दूसरी ओर सुभाष चन्द्र बोस की पुण्यतिथी मनाई गयी। आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन एवं माँ माधुरी वेलफेयर फाउण्डेशन मे संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज में ऐतिहासिक चौराहे सुभाष चौराहे पर फाउण्डेशन के सचिव जय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सामाजिक दूरी का ध्यान देते हुए एवं सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्पण करते हुए।

जान को जोखिम डाल कर रास्ते से निकलने को मजबूर राहगीर

बाराबंकी। बारिस से रास्ते हुआ ध्वस्त। आवगमन में हो रही लोगो को दिक्कते। जान को जोखिम में डाल कर निकल रहे राहगीर कभी भी हो सकता बड़ा हादसा।

मामला विकास खंड त्रिवेदीगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत जौरास गांव से गंगागंज जाने वाला रास्ता दे रहा दुर्घटना को दावत। नही पड़ती किसी जिम्मेदार की नजर। जौरास से भदूवा चौराहे पर जाने वाला रास्ता 1995 में बनाया गया था। जिसके बाद उस रास्ते की आज तक किसी प्रकार की मरम्मत नही करवाई गई। रास्ते के बीच पानी निकास के लिये हियुम पाइप डाल कर ऐसे ही रास्ता निकाल दिया गया था। ग्राम सभा की लापरवाही के चलते पुलिया के निर्माण नही कराया गया था। उसी लापरवाही का नतीजा भुगत रहे ग्रमीण। आज रास्ते मे निकलने में खतरा बना रहता है। तेज बारिश होने से कच्ची पटाई सहित पाइप लाइन बह गई। और रस्ता पूरा धस गया। जिससे लोगो को आने जाने में बड़ी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है। वही रस्ते के धसने के बाद ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला।

प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित, कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं

प्रदेश में 331 बाढ़ शरणालय तथा 748 बाढ़ चैकी स्थापित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आज यहां लोकभवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ राहत का कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए बजट की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारीयों को निर्देश दिये कि बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जल बहाव के कटान से प्रभावित भूमि के समीप स्थित स्कूल व पंचायत भवनों में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों हेतु शरणालय न बनाने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित जनपदों में पशुओं के चारे-भूसे की उचित व्यवस्था करने के साथ-साथ पशु टीकाकरण का कार्यक्रम समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। श्री राजभर ने बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित है। बाढ़ के संबंध में निरन्तर अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0 की 15 टीमें तथा एसडी0आर0एफ0 व पी0ए0सी0 की 07 टीमें इस प्रकार कुल 22 टीमें तैनात की गयी है। 1,176 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है। बाढ़/अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव व राहत प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। श्री राजभर ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण कराया जा रहा है।

केबिल के तार से युवक ने लगाई फांसी

लखनऊ, संवाददाता। आशियाना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने सोमवार की देर रात अपने घर के बाथरूम में लगी बल्ली में केबिल के तार के सहारे फांसी लगा कर अपन जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक को फंदे पर लटका देख मृतक के परिजनों ने पुलिस को कन्ट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार आशियाना थाना क्षेत्र स्थित भदरूख बंगला बाजार में रहने वाले 18 वर्षीय अभय कनौजिया उर्फ आउवा पुत्र स्व सुनील कुमार ने सोमवार की देर रात अपने घर के बाथरूम में रखी बल्ली में केबिल तार से फांसी लगा ली। युवक को फंदे से झूलता देख मृतक के चाचा अनिल कुमार ने पुलिस को कन्ट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रो या मरो की तर्ज पर 2022 के चुनाव में 351 सीटों का लक्ष्यः सपा

➲ अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा नामक पत्र बाटकर सपा नेता नरेन्द्र सिंह ने मांगा जन समर्थन

➲ अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में घर-घर, जन-जन तक संदेश पहुंचाएंगे सपाई

प्रयागराज। मंगलवार को आगामी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में समाजवादीपार्टी लक्ष्य 351 सीटें लेकर बूथ स्तर पर करो या मरो की तर्ज पर पूरी मजबूती के साथ जुटेगी। समाजवादीपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत 9 अगस्त को प्रदेश की जनता के नाम जारी डिजिटल पत्र में कहा है कि जिस तरह से भारत को अंग्रेजी सत्ता के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को करो या मरो का नारा देकर देश के किसानों, नौजवानों, छात्रों, शिक्षकों, नरेशों, सरकारी कर्मचारियों सहित सभी का आह्वान किया था, उसी तर्ज पर सपा बूथ स्तर पर मजबूती के साथ जुटेगी। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश सचिव नरेन्द्र सिंह ने डिजिटल पत्र को छपवा कर मंगलवार को शहर के कई नामचीन बुद्धिजीवियों, सामाजिक हस्तियों, व्यापारियों आदि को सौंप कर प्रदेश में पुनः अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादीपार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन की अपील की है। अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा पत्रक उच्च न्यायलय के नामचीन अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण बिहारी एडवोकेट, मजदूर नेता के0के0 तिवारी, नैनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री राकेश नारायण हजेला, जगराम स्वीट हाउस के मालिक आदि को सौंपकर सपा के समर्थन की अपील की। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर के पत्रक बांट कर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सहयोग की अपील की। सपा नेता श्री सिंह ने कहा कि देश की विविधता को नष्ट करने की साजिशों के दौर में संवैधानिक मूल्यों को बचाने तथा हर नागरिक का समृद्धि और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए सपा कटिबद्ध है। श्री सिंह ने आगे कहा कि भाजपा शासन में आम आदमी को निराश और हताश होना पड़ा है। तमाम वादे कर सत्ता में आने के बाद भाजपा देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे कर, देश की आर्थिक और सामाजिक दशा को तहस-नहस कर रही है। उन्होने सर्व कल्याण के लिए समाजवाद को ही सही राश्ता सुझाया है। अभियान में शामिल पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने कहा कि भाजपा शासन में हर वर्ग परेशान हैं। उन्होने आगामी 2022 में समाजवादीपार्टी की सरकार बनाने के लिए हर वर्ग से अपील की है। सपा के जिला प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सपा नेता नरेंद्र सिंह द्वारा डिजिटल पत्र की हजारों प्रतियां छपवाई गई हैं, जिनका वितरण पूरे जनपद में किया जा रहा है। सपा प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी डिजिटल पत्र को पार्टी जनों द्वारा आम जनमानस में भेज कर भी नेतृत्व के संदेश को प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है।

जातिगत उत्पीड़न का आरोप गलत, अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही

प्रदेश में अब तक 13 पुलिसकर्मी शहीद, 124 अपराधी मुठभेड़ में ढेर

लखनऊ। मार्च 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद अपराधियों की धड़पकड़ के लिए अभियान चलाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस क्रम में प्रदेश में अब तक अपराधियों और पुलिस के बीच 6,200 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी है जिनमें 14 हजार से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं. इन मुठभेड़ में अब तक 2,300 से अधिक अभियुक्त और 900 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अपराधियों से मोर्चा लेते हुए 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं जबकि अब तक 124 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं।अगर जातिवार इन अपराधियों का ब्योरा देखा जाए तो, 47 अल्पसंख्यक 11, ब्राह्मण, 8 यादव और शेष 58 अपराधियों में ठाकुर, पिछड़ी और अनसूचित जाति/जनजाति के अपराधी शामिल हैं. प्राप्त खबरों के अनुसार मुठभेड़ की ज्यादातर घटनाएं पश्चिमी यूपी में हुई हैं. मेरठ में अब तक एनकाउंटर में 14 अपराधी मारे गए हैं। मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9 और शामली में 5 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं. पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर आजमगढ़ में हुआ है जहां 5 अपराधी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं. यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं. नवंबर, 2018 में एनजीओ 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी÷ की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन का यह दावा झूठा है कि एनकाउंटर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया गया है,योगी सरकार ने हलफनामे में बताया था कि पुलिस कार्रवाई में मारे गए 48 अपराधियों में 30 बहुसंख्यक समुदाय से हैं जबकि 18 अल्पसंख्यक समुदाय से. यह प्रकरण अभी भी न्यायालय में लंबित है. पिछले वर्ष जनवरी, 2019 में यूपी में हुए एनकाउंटरों के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनकाउंटरों के नजदीकी और गंभीर परीक्षण की जरूरत है। यूपी के एक अपर पुलिस महानिदेशक निजी मुलाकात में मौखिक बताते हैं कि,यूपी पुलिस हर जिले के टॉप टेन अपराधियों को चिन्हित करके सबके लिए अलग-अलग रणनीति बनाकर कार्रवाई की जा रही है. पिछले एक महीने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वैसी अभी तक नहीं हुई थी. पुलिस अपराधियों में कड़ी कार्रवाई कर रही है7 इसमें जात-पांत, धर्म-संप्रदाय नहीं देखा जाता7 वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ के हर मामले की मजिस्ट्रीयल जांच करने का आदेश दिया था, इसी क्रम में यूपी में भी हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है. सरकारी जानकारी के मुताबिक, अब तक अब तक उन 74 इनकाउंटर की मजिस्ट्रीयल जांच पूरी हो चुकी है जिसमें अपराधी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी7 इन सभी मामलों में पुलिस को मजिस्ट्रीयल जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है. इनमें 61 मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मान लिया है. बावजूद इसके कुछ पुराने मामले अभी भी लंबित हैं. वर्ष 2001 में लखनऊ के मड़ियांव थाने में तैनात एक दरोगा ने पुलिस मुठभेड़ में अपराधी आलमगीर को मार गिराने का दावा किया था, घरवालों ने इसे कत्ल बताया मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हुई और 19 साल बाद प्रकरण लंबित है। इसी तरह लखनऊ में अब तक अलग-अलग मामलों में लंबित करीब तीन दर्जन मजिस्ट्रीयल जांचों में हो रही लेट लतीफी से जहां पीड़ित पक्ष प्रशासनिक सिस्टम को कोस रहा है वहीं यह देरी अपराधियों के लिए ढाल साबित हो रही है. यूपी के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं मजिस्ट्रेटी जांच में कई सरकारी पक्ष शामिल होते हैं,अफसरों के लगातार स्थानांतरण होते रहते हैं जिसके चलते वह बयान और साक्ष्यों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वहीं जांच करने वाले अफसरों के कार्यक्षेत्र भी बदलते रहते हैं. यही वजह है कि आने वाला नया अफसर जबतक केस को समझता है उसका तबादला हो जाता है. मजिस्ट्रेटी जांचों के लंबित रहने का यह एक बड़ा कारण है। लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता (क्रिमिनल) अपना निजी सुझाव देते हैं कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें एनकाउंटर जैसे संवेदनशील मसलों की मजिस्ट्रेटी जांच को एक तय सीमा के भीतर समाप्त करने का प्रावधान रखना चाहिए। हालांकि चर्चा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी के गृह विभाग ने सभी जिलों को लंबित मजिस्ट्रीयल जांच को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उपरोक्त खबर की कोई सरकारी पुष्टि नहीं है। इसकी पुष्टि शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से करने का प्रयास किया गया, किन्तु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया है।

एसएसपी के कार्यालय में आयोजित, जनता न्याय दिवस की, हो रही भूरि- भूरि प्रशंसा

इटावा। आकाश तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में,दिनांक 18. अगस्त 2020 पुलिस कार्यालय में जनता न्याय दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वयं रहकर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा न्याय दिवस में पूर्व से सूचीबद्ध मामलों (विवेचना व शिकायती प्रार्थनापत्रों) में वादी एवं विवेचक/जांचकर्ता द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी। आज कुल 08 प्रकरणों से सम्बन्धित विवेचक/जांचकर्ता एवं वादी/शिकायतकर्ता को तलब किया गया था। इस दौरान सभी मामलों में वादी एवं विवेचक उपस्थित हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सभी प्रकरणों को सुना गया तथा 06 प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया गया एवं शेष 02 प्रकरण का अग्रिम न्याय दिवस तक समाधान करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। न्याय दिवस के इस सफल आयोजन पर प्रकरणों से सम्बन्धित आवेदकण एवं वादी मुकदमा द्वारा इटावा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

अब बेटियां बराबर की हकदार

सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के हक में बड़ा निर्णय दिया है। इस फैसले से चारों ओर खुशी की लहर है। न्यायालय ने कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर का हक है, थोड़ा भी कम नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटी चाहे हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में हुए संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे बेटे के समान ही बराबरी का हक है। वास्तव में जब महिलाएं सामाजिक रिश्तों को ताक पर रखकर अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करती भी थीं तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कई महिलाओं के सामने अड़चन पैदा किया करता था। इस वजह से बीते 15 सालों में महिलाओं की एक बड़ी संख्या पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार मांगने से वंचित रह गई। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही दो फैसलों प्रकाश बनाम फूलमती (2016) और दनाम्मा उर्फ सुमन सरपुर बनाम अमन (2018) में विरोधाभास के बाद कानूनी व्यवस्था तय करने के लिए मामला तीन न्यायाधीशों को भेजा गया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह की पीठ ने फैसले में कहा, चूंकि बेटी को जन्म से संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए संशोधित कानून लागू होने की तिथि को पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। तीन सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह दोहराया कि 'बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती है, लेकिन बेटी जीवनपर्यंत बेटी रहती है।' उनके कथन में बेटियों का अपने माता-पिता के प्रति आजीवन स्नेह का भाव नजर आया। उनके इस उद्गार से जाहिर होता है कि बेटियां अपने मातापिता से भावनात्मक रूप से बेटों के मुकाबले कहीं ज्यादा जुड़ी होती हैं। इस टिप्पणी में अतिशयोक्ति और अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा न्यायिक सुधार किया है, जो न सिर्फ बेटी को बराबर का पैतृक अधिकार देता है, बल्कि लैंगिक न्याय को भी नए सिरे से परिभाषित करता है।

वर्ष 2000 में विधि आयोग ने एक रपट में उल्लेख किया कि आम आदमी के फायदे के लिए सभी तरह के संपत्ति-कानून बनाने चाहिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मनुष्य की आजादी और विकास के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। आयोग ने उस कानून को बदलने की भी अनुशंसा की, जो हिंदू अविभाजित संयुक्त परिवार में महिलाओं को सह-कानूनी उत्तराधिकारी होने को रोकता है। तब तक यह अधिकार पुरुष वंशजों, उनकी माताओं, पत्नियों और अविवाहित बेटियों को ही हासिल था। बहरहाल 2005 में संसद ने आयोग की रपट का संज्ञान लिया तथा उसे स्वीकार करते हुए हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में संशोधन पारित किया। नतीजतन बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार मान लिया गया, लेकिन फिर एक पेंच रह गया।

संशोधित कानून के मुताबिक, यदि 9 सितंबर, 2005 को बेटी का पिता जीवित होगा, तभी कानून लागू होगा। पिता के दिवंगत होने की स्थिति में बेटी वंचित ही रहेगी। अब सर्वोच्च अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सभी भ्रमों, स्थितियों और सवालों पर विराम लगा दिया है। फैसला दिया गया है कि पैतृक संपत्ति में सह-हिस्सेदारी हिंदू महिला का 'जन्म' से ही अधिकार है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ-साथ अन्य लोग आते हैं। हरेक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते समय में भी हमारे देश में बेटियों को पराया समझा जाता है, इसलिए इन्हें लोग अपनी संपत्ति का हकदार नहीं मानते हुए अपनी संपत्ति को बेटों के नाम कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद किस लड़की पर क्या मुसीबत आ जाए कि उसे अपनी पैतृक संपत्ति की कब बेहद जरूरत पड़ जाए, यह कोई नहीं विचारता है। लेकिन हमारे देश में पैतृक संपत्ति के विवाद के जितने मामले, लड़ाई-झगड़े भाइयों के सामने आते हैं, उतने या यूं कहें कि भाई-बहनों के नामात्र के ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हकदार बनाने के लिए हाल ही में एक शानदार फैंसला सुनाया है, लेकिन हमारे देश की लड़कियां अपने माता-पिता की संपत्ति पर कभी भी हक जमाने की कोशिश नहीं करतीं। हां, कुछ लड़कियां शादी के बाद दहेज लोभियों के दबाव में अपनी पैतृक संपत्ति से अपना हिस्सा मांगने की मांग करती हों। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लड़कियों को राहत मिल सकती है जो किसी मजबूरी के कारण अपनी पैतृक संपत्ति पाना चाहती हो या फिर उनकी पैतृक संपत्ति के गलत रिश्तेदारों, रास्ता भटक चुके भाइयों द्वारा इसका दुरुपयोग का खतरा हो। सामाजिक ढांचा और कानूनी पक्ष यह है कि बेटी का ससुराल की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं होता। विवाह में कटुता आने पर पति अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से महज गुजारा भत्ता ही देता है, मगर ससुराल की चल-अचल संपत्ति पर उसका हक नहीं होता। ऐसे में अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने से उसकी स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष भी जानना चाहा था और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने केस में कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए इसे बेटियों का मौलिक अधिकार जैसा माना। सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला आते ही सोशल मीडिया में तमाम प्रतिक्रियाएं हुई। किसी ने इसे उनके सम्मान से जोड़ा तो कोई इसे बराबरी का अधिकार मान रहा है। खैर हर किसी ने तहेदिल से इसको अपनाया, जो दर्शाता है कि अब लोगों की सोच में काफी बदलाव आ रहा है। असल में यह फैसला बदलती सोच का प्रतीक है। बेटी अपना हक ले या छोड़े, यह उसका फैसला होगा। अगर उसे जरूरत हो और तब भी उसे अधिकार न मिले तो यह अन्याय होगा। सांसद व वकील मीनाक्षी लेखी के शब्दों में, 'इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया जा रहा है। यह हमारे परिवार और समाज की ताकत दिखाता है कि समय के अनुसार हमें बदलना भी आता है। बराबरी के अधिकार को हम सही मायनों में मानते हैं और नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं।'' अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कितने लोग अमल करते हुए बेटा-बेटी में अंतर न समझते हुए, अपनी बेटी या बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाते हैं? कानून के जानकार मानते हैं कि भारतीय सामाजिक स्थिति के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण फैसला है,?जिसके दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे और इससे महिलाओं की समाज में स्थिति मजबूत होगी। निश्चय ही शीर्ष अदालत के फैसले से विवाहित बेटियों को संबल मिलेगा। देखा जाए तो यह निर्णय तो संविधान में तब जोड़ा जाना चाहिए था, जब संविधान पर बहस चल रही थी और समानता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। चलिए देर आयद, दुरुस्त आयद।

सम्पादकीय

मानव विकास सूचकांक में पहली बार गिरावट की संभावना

यूएनडीपी के अनुसार कोरोना महामारी के व्यापक प्रभाव के कारण 1990 के बाद पहली बार भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों के मानव विकास सूचकांक में गिरावट आनेवाली है। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त भारित सूचकांक है, जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा ये तीन सूचकांक शामिल हैं। वैसे तो कोरोना महामारी का मानव के स्वास्थ्य पर ही सीधा आक्रमण होने के कारण स्वास्थ्य सूचकांक में ही गिरावट अपेक्षित थी किंतु लॉक डाउन के कारण रोजगार और आमदनी में गिरावट के कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावट के कारण जीवनस्तर सूचकांक में गिरावट तयशुदा है। यह पूछा जा सकता है कि शिक्षा सूचकांक में गिरावट किस प्रकार से आएगी। इसका कारण यह है कि शिक्षा सूचकांक में स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है। दुनिया के 161 देशों के स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद होने से शिक्षा के अभाव में शिक्षा सूचकांक में चार प्रतिशत की गिरावट आनी है। इस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इन तीनों के ही सूचकांक में गिरावट के कारण मानव विकास सूचकांक में गिरावट निश्चित है। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने कोरोना के विश्वव्यापी फैलाव के प्रारंभिक चार महीनों के फैलाव के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में उक्त चिंता व्यक्त की थी। दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीमारी से बचाव के चिकित्सा उपाय अपनाने के बावजूद 16 अगस्त, 2020 तक दुनिया के 188 देशों के 21 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं जिनमें से 7.65 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम के तहत आर्थिक असमानता में कमी को भी शामिल किया है। आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सबसे पहले दुनिया से गरीबी और भुखमरी की समाप्ति होनी चाहिए। यही कारण है कि यूएनडीपी के 1990 से प्रारंभ किए गए सहस्राब्दि विकास लक्ष्य कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन को प्रथम लक्ष्य रखा गया था। 2016 से प्रारंभ किए गए धारित विकास लक्ष्यों के कार्यक्रम में भी 2023 तक सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन प्रथम लक्ष्य है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने गरीबी को तीन वर्गों में विभाजित किया है। पहला अत्याधिक गरीबी, जिसमें प्रति व्यक्ति आमदनी 1.90 डॉलर से कम रहती है। दूसरी, सामान्य गरीबी, जिसमें प्रति व्यक्ति आमदनी 1.90 डॉलर से 3.20 डॉलर के बीच रहती है तथा तीसरी कम गरीबी, जिसमें प्रति व्यक्ति आमदनी 3.20 डॉलर से 5.00 डॉलर के बीच रहती है। 15 अगस्त तक कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया के नए 10 करोड़ लोग अत्याधिक गरीबी की स्थिति में आ चुके हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण वस्तुओं कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण 26 करोड़ नए लोग सामान्य गरीबी की स्थिति में आ गए हैं। धनी लोगों पर कोरोना का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण दुनिया में आर्थिक विषमता में बढ़ोतरी हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्था के देशों में दक्षिण एशिया एवं मध्य अफ्रीकी सहारा देशों गरीबी और आर्थिक विषमता में अधिक वृद्धि हुई है। भारत में लॉक डाउन घोषित करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि मध्य मई तक कोविड-19 जीवाणु कमजोर हो जाएंगे इससे 30 जून तक इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा किंतु यह अनुमान गलत निकला। कोराना का संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता ही गया तथा 16 अगस्त तक बढ़ते हुए 26 लाख व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले चुका था। अभी तक 50 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से भारत का आर्थिक विकास पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 1.0 प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ऋणात्मक भी हो सकती है। भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल और मई 2020 में 23 प्रतिशत थी। यद्यपि जून महीने से इसमें गिरावट देखी जा रही है। इसके बावजूद सीएमआईई के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर के 8.0 से 8.5 प्रतिशत के मध्य रहने की संभावना है। भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक विषमता में भी बढ़ने की संभावना है। यूएनडीपी के धारित विकास लक्ष्यों में भी वर्ष 2020 के लिए निधार्रित लक्ष्यों के पूरी होने की संभावना नहीं के बराबर है। पिछले सप्ताह इंडियन इकॉनॉमिक एसोसियेशन द्वारा भारत के आर्थिक विकास पर कोरोना के संभावित प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार के प्रमुख वक्ता चेन्नई के प्रख्यात मानसिक रोग विशेषज्ञ मोहनराज द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर कोरोना के प्रभाव की चर्चा की गई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉक डाउन के कारण रोजगार और आमदनी का जरिया खोने के कारण या इससे वंचित होने की आशंका के कारण व दिनभर अनचाहे में घर में कैद रहने से बड़ी संख्या में लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इन मानसिक बीमारियों में व्यग्रता, तनाव, उत्तेजना, चिड़चिड़पना, झुंझलाहट, अनिद्रा, निराशा, अवसाद, मानसिक विकार सभी शामिल हैं। चर्चा में कोरोना के कारण मानसिक बीमारी खासकर अवसाद के कारण आत्महत्याओं के उदाहरण भी दिए गए। चर्चा में कोरोना काल में परिपक्व व्यक्तियों के द्वारा गलत निर्णय लेने के भी उदाहरण दिए गए। एक वक्ता ने कहा कि संभवतः कोरोना के प्रभाव के कारण सचिन पायलट सरीखे अनुभवी राजनेता ने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद को त्यागने के बाद 35 दिन में अपनी वर्षो से अर्जित छवि धूमिल कर दी। जहां कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को कमजोर किया है। वहीं पर अर्थव्यवस्था के दो अंग अप्रभावित रहे, पहला शेयर बाजार और दूसरा, चालू लेखा घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार। शेयर बाजार को कारपोरेट सेक्टर का प्रतिनिधि कहा जाता है और बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयरों के सूचकांक सेंसैक्स शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाता है। 23 मार्च को सेंसैक्स 25,981 बिन्दु पर था।

कृषि क्षेत्र के विकास की जरूरी पहल

आजकल सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर दिख रही है. कृषि और किसानों से जुड़े एक के बाद एक लगातार कई बड़े फैसले लिये जा रहे हैं. सरकार इन फैसलों को चरणबद्ध कड़ी के रूप में पेश कर रही है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होंगे और साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगे. कोविड-19 महामारी के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र भारी संकट में हैं, उस समय कृषि क्षेत्र कुछ उम्मीद दिखा रहा है. यही वजह है कि सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र पर बढ़ गया है. इसके लिए सरकार ने कृषि मार्केटिंग सुधारों को लागू करने के लिए तीन अध्यादेश जारी किये. साथ ही अब एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने के साथ ही उस पर अमल भी शुरू किया दिया है. इस फंड के तहत चार साल के भीतर किसानों और कृषि से जुड़े कारोबार के लिए एक लाख करोड़ रुपये के रियायती कर्ज मुहैया कराये जायेंगे. चालू साल (2020-21) में इसके तहत 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया जायेगा, जबकि अगले तीन साल तक हर साल 30,000 करोड़ रुपये के कर्ज मुहैया कराये जायेंगे. इस कर्ज पर सरकार तीन फीसदी की ब्याज सब्सिडी देगी. इस फंड के जरिये किसानों को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की सुविधा स्थापित करने, पैकेजिंग यूनिट लगाने, ग्रेडिंग शेड बनाने, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी भंडारण सुविधाएं स्थापित करने और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं स्थापित करने के लिए कर्ज दिये जायेंगे. सरकार का दावा है कि इसके जरिये किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और आमदनी बढ़ने के साथ ही उनको आंत्रप्रेन्योर के रूप में स्थापित कि जा सकेगा. ग्रामीण आबादी के कौशल का बेहतर उपयोग करने के साथ वहां रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया कराये जा सकेंगे. अब एग्री टेक, एग्री बिजनेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ), सहकारी समितियों और किसानों व बिजनेस इकाइयों को कर्ज दिया जा सकेगा. किसी भी कर्ज की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये रखी गयी है. यह कर्ज निजी बैंकों के जरिये दिया जायेगा और उनके साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जायेंगे हैं. कर्ज का कोऑर्डिनेशन का काम नाबार्ड करेगा. यानी सरकार पूरी तैयारी के साथ इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कामयाब करना चाहती है. उसका मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में एक तरह की औद्योगिक और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की क्रांति आ जायेगी, जो किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगी. वैसे देखने सुनने में यह फार्मूला बहुत आकर्षक लगता है. लेकिन असली चुनौती इसे जमीन पर उतारने की है. इसके साथ ही यहां यह बात साफ करनी जरूरी है कि यह फंड कर्ज है और इसमें सरकार का जिम्मा जहां क्रेडिट गारंटी देने का है, वहीं वह इस पर ब्याज सब्सिडी देगी. यानी हर साल कुछ सौ करोड़ की ब्याज सब्सिडी ही वह पैसा है, जिसे सरकार को अपने बजट से देना होगा. लेकिन इसे बताया जा रहा है कि सरकार कृषि ढांचागत सुविधाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो पूरी तरह से सच नहीं है. वहीं, क्या देश में कृषि ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए यह फंड काफी है. खुद नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि ढांचागत सुविधाओं पर छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की जरूरत है. यह निवेश करने की क्षमता किसानों की नहीं है, क्योंकि अधिकांश किसानों की जोत का आकार छोटा है और 85 फीसदी किसान एक हेक्टेयर से भी कम भूमि के मालिक हैं. देश में जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर पर आ गया है. ऐसे में किसानों की खुद की क्षमता कर्ज लेकर प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने या गोदाम बनाने की नहीं दिखती है. ऐसे में उनके ग्रुप या सहकारी समितियां यह काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले यह ग्रुप स्थापित करने होंगे. हालांकि, देश में लाखों सहकारी समितियां हैं और काम भी कर रही हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी समितियों की है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और उनको चलानेवाले लोग तकनीकी या प्रबंधन के मामले में दक्ष नहीं हैं. इसलिए इस गैप को पूरा करना सरकारी की सबसे बड़ी चुनौती है. साथ ही कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में सहकारी समितियों को बेहतर स्वायत्तता हासिल नहीं है और उन पर राजनीतिक लोगों या प्रशासनिक अधिकारी काबिज रहते हैं. बेहतर होगा कि सरकार पहले उन परिस्थितियों को तैयार करे, जो किसानों को आंत्रप्रेन्योर बनाने की तरफ ले जाती हैं. इसमें देश में कई सफल उदाहरण भी हैं. अमूल यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) का उदाहरण हमारे सामने है, जिसे अकेले गुजरात में तीस लाख किसान दूध की आपूर्ति करते हैं और सही मायने में वही इसके मालिक भी हैं. वे अपने दूध की बेहतर कीमत पाते हैं. इस तरह की कई अन्य राज्य दुग्ध फेडरेशन हैं, जो कामयाब हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में नाकाम संस्थाएं भी हैं. हालांकि, विकल्प के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का फोकस देश में दस हजार एफपीओ स्थापित करने पर है और उसके लिए संसाधन भी मुहैया कराये जा रहे हैं. इसका जिम्मा नाबार्ड और स्माल फार्मर एग्रीबिजनेस कंसोर्सियम को दिया गया, जो कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है. लेकिन अभी जो एफपीओ काम कर रहे हैं, उनके कारोबार का आकार बहुत कम है और बेहतर प्रदर्शन करनेवाले एफपीओ की संख्या भी सीमित है. एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बेहतर शुरुआत तो हो सकता है. लेकिन जब तक सरकार इसे जमीन पर लागू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती है और इस कर्ज को लेकर परियोजनाएं स्थापित करनेवाले कुशल लोगों को तैयार नहीं करती है, तो इसका मकसद पूरा होना मुश्किल है।

क्या हैं नई शिक्षा नीति के लक्ष्य विश्वगुरु या सस्ता श्रम

बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) एक रोज एकदम से आई और एकदम से ही स्वीकार ली गई। कोई चिल्ल-पों नहीं हुआ। तर्क यह कि पहले ही राष्ट्रव्यापी, बहुस्तरीय कन्सलटेशन और सुझाव आदि हो चुका है और इस तरह अब यह फुल-प्रूफ शिक्षा नीति जनाकांक्षाओं और जन-अपेक्षाओं से ओत-प्रोत है। दावा है कि इसे समय की नब्ज को पहचान कर बनाया गया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका आमतौर पर संदेह किया जा रहा था। पर संदेह न करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रियान्वयन को मौजूदा सरकार और उसकी कार्य प्रणालियों व नीति- रीति के बरक्स देखना भी तो जरूरी है। सन् 1950 से हम शिक्षा को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करके, एक-के-बाद-एक नीतियां और कार्यक्रम बनाते चले आए हैं। उन दिनों हमने दम ठोंककर, दस सालों में सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का वादा किया था। तब तो राजनीतिक प्रतिबद्धता भी थी, अब वह थोड़ी संदेहास्पद है। सन् 1950 से गिनें तो 70 साल हो गए हैं, लेकिन नतीजा सिफर से थोड़ा ही आगे आया है। अब श्नई शिक्षा नीति-2020श् के अनुसार दस सालों में स्कूल से बाहर हुए 2 करोड़ बच्चों को वापस लाने का विशाल लक्ष्य सचमुच विशाल है। यह न होने जैसी बात का ही दुहराव मात्र है। एनईपी-20 बाकी नीतियों की तरह ही एक गोल-मोल नीति है। समय के साथ यह समय की जरूरतों को पूरा करने वाली नीति ही कही जा सकती है। यह नीति वैश्विक विकास एजेंडा की बात करती है और इसीलिए 2030 तक सभी देशों की तरह, सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने के लक्ष्य को सामने रखती है। भारत के लिए यह वैश्विक एजेंडा, विश्वबैंक के उस एजेंडे से कदमताल करता है जिसकी साफ हिदायतें हैं कि राज्य का ऐसा कल्याणकारी स्वरूप (वेल्फेयर स्टेट) धीरे-धीरे खत्म करते जाना चाहिए जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देता है। जनता को स्वयं सक्षम और उपभोक्ता बनने की दिशा में ले जाया जाना चाहिए। स्किल इंडिया के बाद एक बार फिर ज्ञान और तकनीकी के नाम पर आत्मनिर्भरता के जुमले के साथ स्कूल शिक्षा को श्स्किल बेस्ड नॉलेजश् (हुनर आधारित ज्ञान) और रिसोर्स (संसाधन) से जोड़ने की बात बहुत ही चतुराई से कही गई है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुनियादी तालीम के साथ गांधी का भी सपना आत्मनिर्भर समाज बनाने का रहा था जिसमें शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, जीवन और समुदाय से जुड़ी, श्रम के प्रति सम्मान सिखाने वाली, ग्राम-स्वराज की ओर ले जाने वाली माना गया था, लेकिन इस नीति में जो प्रावधान हैं वे ग्राम-स्वराज के लिए नहीं, बल्कि बाजार राज के लिए जान पड़ता है। स्कूल के दौरान ही वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यावसायिक प्रशिक्षण), कौशल उन्नयन और विषय की तरह उनकी पढ़ाई व प्रशिक्षण, शिक्षा और उसके अनुशासन में विविधता की बात तक तो ठीक है, लेकिन इसकी मंशा पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा श्मानव संसाधन विकास मंत्रालयश् की ही एक रिपोर्ट कहती है कि श्ड्रॉप-आउट रेटश् (स्कूसल छोड़ने वालों की दर) 40 फीसदी है, हर साल नामांकित में से 50 फीसदी बच्चे ही 8वीं तक पहुंचते हैं, उनमें भी 17 फीसदी लड़कियां 14 साल या 8 वीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, 12 वीं तक सिर्फ 10फीसदी बच्चे पहुंचते हैं। छूटने वाले और पहुंचने वाले ये कौन बच्चे हैं यह किसी से छुपा नहीं है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों का शिक्षा के इस संसार में क्या हश्र है इसके लिए ये आंकड़े पर्याप्त हैं। अब आठवीं (14 साल की उम्र) तक उन्हें किसी कौशल से नवाजने का मतलब आखिर क्या है? क्या एक बार फिर कामधंधों के हिसाब से जातियों वाला समाज बनने जा रहा है? क्या बच्चे अपने पुश्तैनी काम-धंधों में धकेल दिये जाएंगे? क्या उन्हें एक ऐसे मानव संसाधन के रूप में तैयार करके छोड़ दिया जाएगा जो बाद में कॉरपोरेट जगत के लिए कल-पुर्जे की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या शिक्षा इसी का नाम है जिसके लिए इतनी महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है? या फिर ज्ञान के श्सुपर पॉवरश् वाले जुमले की आड़ में यह सस्ते श्रम उपलब्ध कराने वाले बाजार खड़े करने की दूरगामी योजना है? सवाल कई हैं, क्योंकि मंशा में खोट है। छह से 14 साल तक के शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 3 से 18 साल कर दिया गया है और अब मध्यान्ह भोजन के साथ नाश्ते का भी वादा किया गया है। इसे कुछ मायनों में ठीक कहा जा सकता है, लेकिन पिछला कानून ही जब कुछ नहीं कर पाया तो अब सिर्फ प्रावधान करने भर से क्या हो जाएगा? क्या ही अच्छा होता यदि तीन से 18 साल के इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए भी तुरत-फुरत कानून बना दिया जाता। जब तक यह नहीं होता, यह दिखावटी झुनझुने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। बच्चों के सीखने के शुरुआती महत्वपूर्ण सालों (3 से 6 साल) को औपचारिक ढांचे में बांधकर उन्हें स्कूल की दृढ़ संरचना के भीतर लाना एक तरह से उदार, लचीले, नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप से सीखने के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उसका ढांचाकरण और केंद्रीय नियंत्रण एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि कहीं यह एक वैचारिक घुट्टी पिलाने की कवायद का हिस्सा तो नहीं है? नई नीति एक लोक-लुभावन बयान देती है कि प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। यह हर सरकार कहती है और उसके नियमन का एक ढांचा भी बनाती है, लेकिन दूसरे रास्ते से वही सरकार निजी स्कूलों को तमाम तरह की रियायतें देती है, फीस के बहाने लूट की खुली छूट देती है। अब फिर बाजारीकरण और निजीकरण को रोकने की खातिर सरकार की तरफ से कोई नियामक और नियंत्रक ढांचे का जिक्र इस नीति में नहीं है, बल्कि इसके उलट, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (सार्वजनिक-निजी गठबंधन) को बढ़ावा देने की बात करती है। तमाम कॉरपोरेट फाउंडेशन, पाठ्यक्रम बनाने से लेकर, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन, मूल्यांकन और निगरानी के काम में आगे आ रहे हैं और सरकार के सलाहकार की भूमिका में हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण की डाइट जैसी सरकारी महत्वाकांक्षी संस्थाओं को दरकिनार कर निजी संस्थान शिक्षा की डिग्रियां बांट रहे हैं। निजी दानदाता संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र की कमान सौंप कर एक तरह से निजीकरण, व्यवसायीकरण और कोपोरेटीकरण को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शिक्षा का भार परिवारों पर पड़े और राज्य की जवाबदेही धीरे-धीरे खत्म हो।

उससे भी आगे विरोधाभास तो यह है कि युक्ति-युक्तकरण के नाम पर अकेले मध्यप्रदेश में ही हजारों स्कूल बंद करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके नाम पर बजट कटौती और मर्जर का काम तेजी से चल रहा है। नई शिक्षा नीति-2020 इस पर चुप्पी साधे दिखती है। सकल घरेलू उत्पाोद (जीडीपी) का 6 फीसदी शिक्षा में खर्च करने का वादा तो है पर ये जुटाया कहां से जाएगा, इस पर कोई खुलासा नहीं है। क्या विश्व बैंक और कॉरपोरेट पूंजी मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था चलाने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ से ऋण आ रहा है और दूसरी तरफ से विचार। ये जुगलबंदी गरीब-गुरबा के बच्चों के लिए क्या समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की चिंता करेगी या कारपोरेट धर्म निभाएगी! समय की मांग है बाजार, बाजार और बाजार। और सब जानते हैं कि यह सरकार समय की नब्ज पहचानती है। नई शिक्षा नीति में इस बाजार की जरूरत को पूरा करने और भारत में सस्ता, कुशल श्रम उपलब्ध कराने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं।

सीपीएल 2020 के जरिए होगा टी20 क्रिकेट का आगाज

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। कैरेबियाई सरजमीं पर आज यानी 18 अगस्त से टी20 लीग की शुरुआत होने जा रही है। कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी [illegible] का 2020 का आगाज 18 अगस्त से हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस टी20 लीग में भी तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। सीपीएल के इस सीजन के सभी मैच त्रिनिदाद में ही खेले जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण ऐसा किया गया है। ऐसा पहली बार है, जब सिर्फ त्रिनिदाद में ही मुकाबले खेले जाएंगे। यहां तक कि त्रिनिदाद में सिर्फ पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम और तारौबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में सीपीएल के इस सीजन के सभी मुकाबले खेले जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच ये पहली टी20 लीग है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। सीपीएल की शुरुआत 18 अगस्त से हो रही है, जबकि कैरेबियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 33 मैच खेले जाएंगे, जिसमें कुछ डबल हैडर (एक दिन में दो मैच) मैच भी होंगे। वहीं, सीपीएल के फाइनल के ठीक 8 दिन बाद 19 सितंबर को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेला जाएगा। सीपीएल 2020 का आगाज मैच ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 19 अगस्त की सुबह भारतीय समयानुसार साढ़े 3 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का दूसरा मैच बारबाडोस और सेंट किट्स की टीमों के बीच होगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के सह-मालिकाना हक वाली टीम ट्रिनबागो से काफी उम्मीद हैं कि टीम इस बार भी खिताब जीतेगी।

हिटमैन के अलावा इन खिलाड़ियों के लिए भी हुए खेल रत्न देने की सिफारिश

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश इस साल के खेल रत्न अवॉर्ड के लिए की गई है।नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड के लिए बनाई गई चयन समिति ने हिटमैन रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश खेल सम्मान के लिए किया है। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्डस कमेटी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के अलावा रेस्लर वीनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा, पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलु के नाम की भी सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न के लिए की है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के

चौथे क्रिकेटर होंगे। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर(1997-98), एमएस धौनी (2007) और विराट कोहली(2018) को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार को द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश की थी, जबकि मंगलवार को समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के नामों को भी पक्का किया है। वीनेश फोगाट भी खेल रत्न के लिए की गई सिफारिश में रोहित को टक्कर दे रही हैं। वीनेश ने पिछले कुछ टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। वीनेश अब तक 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें से दो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं, जबकि एक एशियन गेम्स में जीता है। वहीं, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा की बात करें तो उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में और फिर टीम के साथ भी गोल्ड जीता था। वहीं, एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलु की बात करें तो उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में हाई जंप में गोल्ड जीता था। भारतीय टीम के सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा ने बीते कुछ साल में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। एक क्रिकेटर के तौर पर ही नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी रोहित शर्मा ने खुद को साबित किया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनाई गई चयन समिति, जिसमें खुद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं, उसने रोहित शर्मा को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि रोहित ने पिछले साल खेले गए वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 में भारत के लिए 5 शतक ठोके थे। हालांकि, भारतीय टीम सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।

पापा धोनी और बाइक राइड्स को मिस कर रहीं जीवा

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनैशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 15 अगस्त शाम को इंस्टाग्राम पर अपना फेवरेट गाना पोस्ट कर ऐलान कर दिया कि उन्हें सात बजकर 29 मिनट से रिटायर्ड समझा जाए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने धोनी के रिटायरमेंट को लेकर कहा कि अब भारतीय क्रिकेट को उनकी अहमियत का पता चलेगा। धोनी के रिटायरमेंट के फैसले से हर कोई हैरान था और अब सभी अपने फेवरेट क्रिकेटर को मिस कर रहे हैं। मिस करने वालों लोगों में उनकी प्यारी बेटी और सोशल मीडिया स्टार जीवा भी है। उनके अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई है जिसमें उनके साथ उनके पापा एमएस धोनी दिख रहे हैं। धोनी के संन्यास के ऐलान के बाद जीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट से यह पहली फोटो शेयर हुई है। इसके कैप्शन में धोनी के बारे में लिखा गया है, मिस यू एंड बाइक राइड्स। फोटो में जीवा एक बैग के ऊपर बैठी दिखाई दे रही हैं, वहीं धोनी उनके साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को जीवा और धोनी दोनों के ही फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। धोनी के अलावा साक्षी और जीवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर मस्ती के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। जीवा सोशल मीडिया पर भारत की सबसे फेमस सिलेब्रिटी किड्स में से एक हैं। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जिससे पता चलता है कि वो कितनी फेमस हैं। यह अकाउंट उनके माता-पिता साक्षी और धोनी ही चलाते हैं। अभी हाल में जीवा धोनी एक फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गईं थीं। दरअसल इस फोटो में उनकी गोद में एक बच्चा दिखाई दे रहा था। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि धोनी और साक्षी के घर एक और नया मेहमान आया है। इसके अलावा कई फैन्स यह भी कह रहे थे कि यह बच्चा हाल ही में पिता बने हार्दिक पांड्या का है। हालांकि साक्षी ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा था।

धोनी अपना फेयरवेल मैच कहां खेलेंगे

वीवीएस लक्ष्मण ने बताया जगह का नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और इसके बाद ये बातें भी उठने लगी कि धौनी जैसे महान खिलाड़ी ने फेयरवेल मैच भी नहीं खेला। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इच्छा व्यक्त की थी कि रांची में एम एस धौनी का के विदाई मैच का आयोजन हो। अब दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को विश्वास है कि धौनी का फेयरवेल मैच चेपक में आयोजित किया जाएगा। एम एस धौनी का जन्म रांची में हुआ, लेकिन पिछले कई साल से चेन्नई उनका घेरलू मैदान जैसा है। वो आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2008 से लीड कर रहे हैं और तीन खिताब भी दिला चुके हैं। धौनी का चेन्नई में ऐसा प्रभाव है कि वहां के क्रिकेट फैंस उन्हें थाला या थलाइवा कहते हैं।

लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के शो क्रिकेट कनेक्टेड में कहा कि हम सबको ये पता है कि माही सीएसके को लेकर काफी भावुक हैं। ये टीम सबसे सफल फ्रेंचाईजी माही की लीडरशिप में ही बनी है। वो इस टीम को खिताब दिलाने से लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे वो सीएसके की कप्तानी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि धौनी के हर एक मूवमेंट को काफी बारीकी से देखा जाएगा। धौनी जितना वक्त मैदान पर बिताएंगे उस हर पल का फैंस आनंद लेंगे। उन्होंने कहा कि अब ये तय है कि धौनी भारतीय जर्सी में नहीं दिखेंगे ऐसे में उन्हें विश्वास है कि ये महान विकेटकीपर-बल्लेबाज अपना आखिरी मैच सीएसके के लिए आइपीएल में खेलेगा जिसका आयोजन चेपक में किया जाएगा। यानी वो आइपीएल में ही अब अपना फेयरवेल मैच खेलेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे लगता है कि एम एस धौनी जब सीएसके के लिए आखिरी मैच खेलेंगे वही उनका विदाई यानी फेयरवेल मैच होगा। मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था मुझे लगता है कि धौनी का विदाई मैच चेपक में आयोजित किया जाएगा। यही नहीं सभी क्रिकेट फैंस ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनियाभार के धौनी के आखिरी मैच को देख रहे होंगे। धौनी के आइपीएल भविष्य को लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। धौनी इस साल इस टीम की अगुआई कर रहे हैं, लेकिन वो आइपीएल 2021 में खेलेंगे या नहीं इसका पता फ्रेंचाइजी के अधिकारियों को भी नहीं है।

पाकिस्तानी कप्तान का बयान- धोनी की विरासत को हमेशा याद रखेगी क्रिकेट की दुनिया

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान टीम के सीमित ओवरों के कप्तान बाबर आजम ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय टीम के महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने जो विरासत छोड़ी है, उसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। बाबर आजम का ये बयान उस समय आया है जब एमएस धौनी ने अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर को 15 अगस्त को अलविदा कहा है। धौनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए संन्यास की घोषणा की थी। बाबर आजम ने एमएस धौनी को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ÷उल्लेखनीय करियर के लिए एमएस धौनी आपको बधाई क्रिकेट जगत में आपके नेतृत्व, लड़ाई की भावना और विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। मैं आपके जीवन के हर पहलू में पर्याप्त प्रकाश और चमक की कामना करता हूं।÷ धौनी ने इंस्टाग्राम पर संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा था कि भरपूर प्रेम और समर्थन के लिए आप सभी

का धन्यवाद। मुझे 7 बजकर 29 मिनट के बाद रिटायर समझा जाए। साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले महेंद्र सिंह धौनी ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 के दौरान खेला था। ये मुकाबला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें भारत को करीबी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में धौनी 50 रन बनाकर आउट हो गए थे और टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। धौनी इसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आए और फिर एकाएक वनडे और टी20 क्रिकेट से भी दूरी बनाने का फैसला कर लिया। एमएस धौनी ने जैसे ही संन्यास का ऐलान किया। कुछ ही मिनटों के बाद सुरेश रैना ने भी उनको ज्वाइन किया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धौनी की महानता किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने देश को साल 2007 में टी20 विश्व कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था। इस तरह धौनी दुनिया के एकमात्र कप्तान बने थे, जिन्होंने तीनों आइसीसी ट्रॉफियां देश को दिलाई थीं।

आईपीएल 2020 की मुख्य प्रायोजक का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 2020 के सीजन के लिए मुख्य प्रायोजक का ऐलान हो गया है। ड्रीम इलेवन कंपनी ने आइपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ये कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी को 2020 के आइपीएल के बतौर मुख्य प्रायोजक रिप्लेस करेगी। आइपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ड्रीम इलेवन ने वीवो की तरह मोटी बोली लगाई है। आइपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाना है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ ने वीवो के साथ अपनी साझेदारी तोड़ ली थी, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसी विवाद के बाद भारत में चीनी सामानों के खिलाफ बहिष्कार शुरू हो गया था। ऐसे में बीसीसीआइ ने विवादों से बचने के लिए वीवो के साथ 2020 के लिए साझेदारी से समझौता कर लिया था। लीडिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन में टाटा ग्रुप और अनअकेडमी जैसे आइपीएल के मुख्य प्रायोजक के दावेदारों को चित करते हुए बोली लगाई और जीती। इस बोली में दूसरे नंबर पर अनअकेडमी रही, जबकि तीसरे नंबर पर टाटा संस ने बोली लगाई। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपये की बोली के साथ आइपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की डील में बाजी मारी है। हालांकि, वीवो जितना एक साल के आइपीएल के बीसीसीआइ को रकम(एक साल के लिए 440 करोड़) अदा करती थी, उससे कम रकम में बीसीसीआइ को नया स्पॉन्सर मिला है। इससे पहले कहा जा रहा था कि आइपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस ड्रीम इलेवन के अलावा बायजू, अनअकेडमी, टाटा संस और पतंजलि के बीच होगी, लेकिन बायजू और पतंजलि रेस में काफी पीछे रह गईं, जबकि बाजी ड्रीम 11 ने मारी। हालांकि, बीसीसीआइ और ड्रीम 11 के बीच ये करार सिर्फ चार महीने का होगा। इस बात का ऐलान बीसीसीआइ ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि आगे फिर से बीसीसीआइ को वीवो के साथ हाथ मिलाना है।

रिटायरमेंट से बाद आईपीएल में कैसा है धोनी का भविष्य

नई दिल्ली, एजेंसी। अपने फैसलों की वजह से ही अपने क्रिकेट करियर में इतने सफल रहे। एम एस की ये खासियत रही कि वो कभी भी फैसला लेने में कोताही नहीं बरतते थे और सही वक्त पर सही फैसला ही उनकी सफलता का मूलमंत्र रहा। मैदान के अंदर की बात करें या फिर बाहर की उन्होंने अपने हर फैसले से हमेशा ही सबको चौंकाया। बात उनकी शादी की हो या फिर कप्तानी छोड़ने से लेकर रिटारयमेंट लेने तक की, माही ने सारे फैसले अचानक ही किए। 39 साल के सबसे सफल कप्तान ने 15 अगस्त 2020 के दिन अपने 16 साल पुराने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। माही अब ब्लू नहीं बल्कि पीली जर्सी में

आइपीएल में नजर आएंगे, लेकिन कब तक ये साफ नहीं है पर सीएसके फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उनके आइपीएल भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने धौनी के संन्यास के बाद उनसे आइपीएल भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वो सीएसके के लिए खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जब तक चाहें हमारे लिए खेल सकते हैं। सच तो ये है कि हम उन्हें साल 2021 आइपीएल के बाद भी एक खिलाड़ी के तौर पर रिटेन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला धौनी का था और जब वो इस तरह से फैसले करते हैं तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि, हम निश्चित तौर से हम ये आशा करते हैं कि वो सीएसके को छोड़ने का फैसला इस तरह से नहीं करेंगे। विश्वनाथन ने आगे कहा कि धौनी का ये फैसला हमें चकित कर गया, लेकिन उन्होंने कोई भी भावना नहीं दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम और सीएसके को धौनी की कप्तानी में इतनी सफलता मिली क्योंकि उनके विचारों में स्पष्टता थी। शनिवार को भी धौनी के निर्णय में मैं वहीं स्पष्टता देख सकता था।

धोनी से ज्यादा टैलेंटेज हैं रिषभ पंत, उनसे बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं साबित

नई दिल्ली। 23 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहली बार साल 2004 में डेब्यू किया था और 39 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। धौनी के संन्यास लेने से पहले से ही रिषभ पंत को उनका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन लगातार मौके दिए जाने के बावजूद वो खुद को साबित नहीं कर पाए थे। अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का कहना है कि 22 साल की उम्र में रिषभ पंत के पास 23 साल की उम्र में टीम इंडिया में खेलने आए एम एस धौनी के मुकाबले ज्यादा नैचुरल टैलेंट है। वैसे पंत को अपने खराब शॉट्स की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। रिषभ पंत टीम इंडिया के वनडे और टी20 टीम का हिस्सा लगातार रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अब उनकी जगह केएल राहुल को तवज्जो देना शुरू कर दिया है क्योंकि पंत की गैरमौजूदगी में उन्होंने टीम के लिए बखूबी विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका भी निभाई और सफल भी रहे। हालांकि केएल राहुल द्वारा इस भूमिका के निभाए जाने के बाद टीम के पास ज्यादा विकल्प हैं। वहीं दूसरी तरफ आशीष नेहरा का कहना है कि अगर रिषभ पंत अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर पाए तो वो भारत के लिए एम एस धौनी से भी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि आशीष नेहरा ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इतना सबकुछ हासिल करने के लिए रिषभ पंत को उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी एम एस धौनी ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में की है। नेहरा ने आगे कहा कि रिषभ पंत सिर्फ 14 साल की उम्र से सोनट क्लब में थे। यकीन मानिए 22 साल की उम्र रिषभ पंत के पास जितना नैचुरल टैलेंट है।

ईशांत शर्मा सहित 29 खिलाड़ियों के नामों की अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और तीरंदाज अतनु दास सहित 29 खिलाड़ियों की खेल मंत्रालय की चयन समिति ने इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए सिफारिश की है। मंत्रालय के ऑफिशियल अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, क्रिकेटर दीपक हुड्डा और टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण का नाम भी शामिल है। ईशांत शर्मा के करियर की बात करें तो इस तेज गेंदबाज ने 97 टेस्ट में 297 विकेट लिए हैं, जिसमें 11 बार 5 विकेट भी शामिल हैं। ईशांत पिछला मैच इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड में खेले थे। ईशांत के नाम 80 वनडे मैचों में 115 विकेट हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनके लिए कहा था कि इशांत टेस्ट टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और भारत को नंबर-1 टीम बनाने में उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। इसमें कहा गया कि अर्जुन अवॉर्ड की सिफारिश के लिए ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और पूर्व वर्ल्ड चैम्पियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का भी नाम शामिल था लेकिन खेलमंत्री किरेन रीजिजू ने फाइनल निर्णय लेते हुए उनका नाम हटा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाएं पहले खेल रत्न अवॉर्ड पा चुकी हैं। साक्षी ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की वजह से खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया था जबकि मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने की वजह से 2018 में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ यह अवॉर्ड जीता था।

आखिर फिल्मों के जरिए सुशांत को कितनी हुई थी कमाई ?

टैलेंट मैनेजर जयंती से की ईडी ने पूछताछ

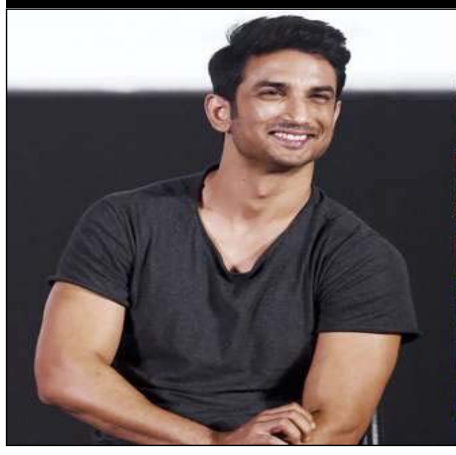

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए दिन बड़े खुलासे होते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। हालांकि इस मामले में जांच ईडी कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार सही कई लोगों से ईडी ने घंटों की पूछताछ करी है। इसी केस में ईडी ने कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जयंती साहा से भी पूछताछ की है। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्रूंद के लिए जयंती साहा काम करती हैं। हालांकि पहले सुशांत का अकाउंट भी वह हैंडल करती थीं। कई फिल्मों में काम सुशांत को उनकी एजेंसी के माध्यम से मिला था। बीते गुरुवार दोपहर को ईडी ने पूछताछ के लिए जयंती को बुलाया था। इस दौरान जयंती साहा से 12 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। इस पूछताछ से यह पता लगाना चाहती थी ईडी आखिर पिछले साल और इस साल कितने प्रोजेक्ट सुशांत को उनकी एजेंसी के जरिए मिले थे। खबरों, सुशांत के अकाउंट से ज्रूंद एजेंसी को 60 लाख का ट्रांजेक्शन भी हुआ था। इसी वजह से जयंती से सवाल इस लेनदेन को लेकर ईडी ने किया। इस मामले में बेहद अहम ईडी की यह पूछताछ को माना गया है। दरअसल इस पूछताछ से इस बात का पता चल सकेगा कि अपनी फिल्मों के जरिए सुशांत ने कितनी कमाई की थी। उन्हें काम करने का मौका कौन सी फिल्मों में मिला था। हालांकि फिल्म दिल बेचारा सुशांत की इस साल रिलीज हुई है। सुशांत के अलावा कई दूसरे सेलेब्स के लिए भी टैलेंट मैनेजर जयंती साहा ने काम किया हुआ है। खबरों के मुताबिक रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे सेलेब्स के साथ भी जयंती साहा ने काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक कई सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को ज्रूंद एजेंसी हैंडल कर रही है। इसलिए जयंती का बयान बहुत मायने सुशांत मामले में रखता है।

आलिया संग रणबीर कपूर के रिश्ते पर रिद्धिमा ने कह दी ये बात

बोलीं- अगर मेरा भाई...

बॉलीवुड के हॉट कपल्स में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप लगातार सुर्खियों में है. इन दिनों आलिया और रणबीर अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर रहे हैं. शूटिंग से इतर दोनों को कई बार एकसाथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा गया है. दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से काफी खुश नजर आते है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर की बहन रिद्धिमा कपूर ने दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी. एक इंटरव्यू में रिद्धिमा कपूर से पूछा गया कि आलिया के बारे में उनका क्या खयाल है और वे रणबीर और आलिया की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगी. इस पर रणबीर की बहन रिद्धिमा ने कहा, मैं क्याकह सकती हूं? मैं खुश हूं अगर मेरा भाई खुश है. और मैं वाकई में अपने भाई को लेकर बहुत खुश हूं. बता दें कि रणबीर कपूर की फैमिली आलिया को पसंद करती हैं. हाल ही में आलिया के पापा महेश भट्ट के बयान ने सबको चौंका दिया था. उन्होंने कहा था कि, जाहिर तौर पर दोनों एकदूसरे से प्यार करते हैं. आपको इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये. मुझे रणबीर कपूर पसंद है और वह बहुत अच्छे इंसान हैं. उन्हें इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है ये उन्हें सोचने की जरूरत है. वहीं, आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ नजर आनेवाली हैं. खबरें हैं कि आ रही है कि फिल्म का पहला लुक अगस्त में जारी हो सकता है. एक्शन-एडवेंचर आधारित यह फिल्म 4 दिसंबर 2020 को रिलीज हो सकती है. इससे पहले फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होनेवाली थी लेकिन विजुअल इफेक्ट्स का काफी काम अभी बाकी है, ऐसे में फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया. मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मास्त्र एक ट्रायोलॉजी है और अयान मुखर्जी भाग 1 और भाग 2 के बीच ज्यादा अंतर नहीं चाहते हैं, और इसलिए, वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी भागों के लिए खाका तैयार हो. धर्मा प्रोडक्शन के तले बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं. फिल्म पांच भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.

बेबस महसूस कर रही हैं सुशांत की बहन श्वेता, एससी से कहा- हर मिनट की देरी दर्द देती है

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दो महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है। मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की उलझन खत्म नहीं हुई है। सीबीआई और ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर याचिका पर फैसला लंबित है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस बीच कोर्ट से अपील की है कि वह अपना फैसला जल्दी सुनाए। श्वेता लगातार इंसाफकी मांग रही है। लेकिन इस लड़ाई में वह कई बार खुद को बेबस, लाचार और असहाय भी महसूस करती हैं। श्वेता ने सोमवार देर शाम और मंगलवार सुबह दो ट्वीट किए हैं। देर शाम के ट्वीट में जहां उन्होंने इंसाफकी लड़ाई में कई बार खुद को असहाय महसूस करने की बात कही है, वहीं मंगलवार सुबह श्वेता ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने के लिए अनुरोध करती हूं। हमें बहुत आशाएं और हम पूर धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हर मिनट की देरी से दर्द और दिल टूट रहा है। ट्विटर पर सोमवार देर शाम श्वेता लिखती हैं, इस बीच कई ऐसे पल हैं, जब मैंने खुद को असहाय महसूस किया है। बेबसी का भाव हावी हो जाता है। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूं कि ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी कीमत पर न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। सुशांत को इंसाफदिलाने की मांग अब लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। हिंदुस्तान के हर कोने से न्याय और सच की जीत की आवाजें आ रही हैं। इसके साथ ही कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और मलेशध्यिा जैसे देशों में भी फैन्स सुशांत को इंसाफदिलाने के लिए आवाज उठा रह हैं। हाल ही श्वेता ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बिलबोर्ड लगाकर सुशांत के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं। श्वेता ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, सुशांत के फैन्स से ऑस्ट्रेलिया में भी इसे मुमकिन कर दिखाया। पूरे महादेश में 7 बिलबोर्ड लगाए गए हैं, जो स्पष्ट संदेश देते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने जहां सुशांत के पिता से भी 4 घंटे की पूछताछ की है, वहीं मंगलवार को सुशांत के सीए और रिया चक्रवर्ती के अकाउंटेंट को भी तलब किया गया है। सुशांत की लाश 14 जून को उनके मुंबई स्थित फ्लैट के बेडरूम में पंखे से लटकी हुई मिली थी। सुशांत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट को यह फैसला देना है कि सुशांत केस की जांच किसके अधीन होगी।

प्रभास और दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म आदिपुरुष

सामने आया फर्स्ट लुक

बाहुबली ऐक्टर प्रभास और पद्मावत ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अगली फिल्म में एकसाथ आने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां बहुत जल्द दीपिका पादुकोण और प्रभास तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष में साथ नजर आनेवाले हैं और अज 18 अगस्त की सुबह-सुबह इस फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। आदिपुरुष मूवी का पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा है, बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाते हुए। वैसे, फिल्म में प्रभाष के लुक को लेकर अब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वह आदिपुरुष के रोल में दिखेंगे। बता दें कि फिल्म की जानकारी मिलते ही इस प्रॉजेक्ट को लेकर फैन्स ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी। बीती शाम डायरेक्टर ओम राउत ने सोशल मीडिया पर प्रभास के साथ बातें करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में ओम राउत कहते नजर आए-हाय प्रभास, क्या तुम कल सुबह की बड़ी घोषणा के लिए तैयार हो? और जवाब में प्रभास ने हां कहते हुए अपना पूरा उत्साह दिखाया। आखिरकार यह घोषणा आज सुबह-सुबह कर दी गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ओम राउत, जो कि एक 3डी ऐक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को हिन्दी और तेलुगू में तैयार किया जाएगा और फिर इले तमिल, मलयालम, कन्नड़ के अलावा कई विदेशी भाषाओं में डब किया जाएगा।

आखिर क्यों किया सारा अली और कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो

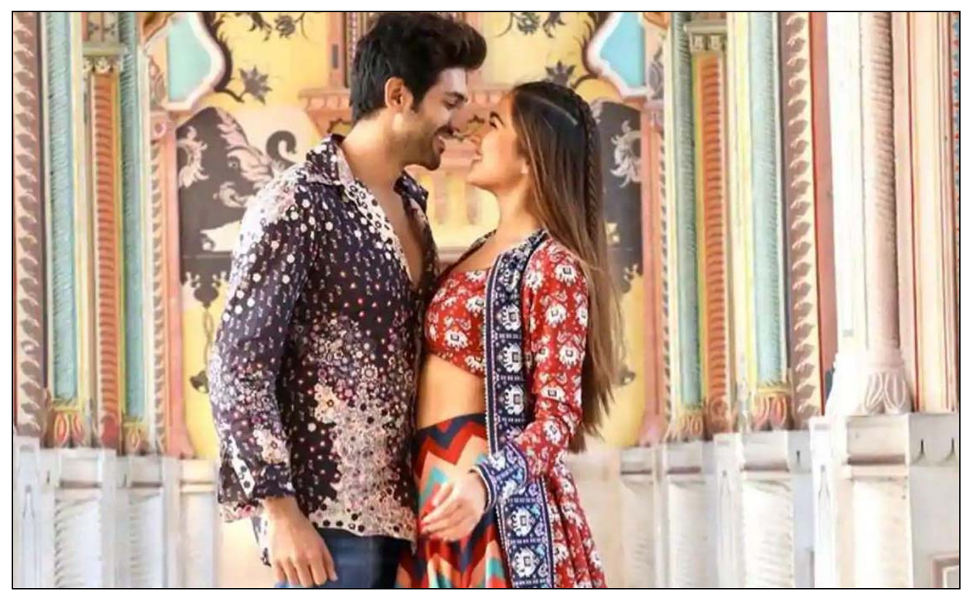

बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और एक्टर कार्तिक आर्यन ने साथ में डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म शलव आज कलश् में साथ काम किया था। अब खबर है कि दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया सारा और कार्तिक अपने पिछले पोस्ट्स को एडिट कर रहे हैं,जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। जब फिल्म लव आज कल की शूटिंग की शुरु हुई तब इंटरनेट पर खबर आने लगी थी कि सारा और कार्तिक आर्यन एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।

ये आलम तब था जब इम्तियाज अली की इस फिल्म की शूटिंग इन दोनों स्टार्स ने शुरू भी नहीं की थी। मगर एक समय ऐसा भी था जब फिल्म के रिलीज होने से पहले दोनों के रास्ते अलग हो गए। वैसे फैन्स को फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आयी थी। वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान वरुण धवन के साथ फिल्म 'कुली नं 1' में नजर आएंगी। कोरोना वायरस के कारण इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था। अभी तक इसकी रिलीज डेट कन्फर्म नहीं हुई है। इसके अलावा सारा अक्षय कुमार और धनुष के साथ फिल्म 'अतरंगी रे' में दिखाई देने वाली हैं। वहीं कार्तिक आर्यन अपने अपकमिंग प्रोजेक्टस 'भूल-भुलइया 2' और 'दोस्ताना 2' के काम में बिजी चल रहे हैं।

सुशांत केस से जुड़े गवाहों की हो सकती है हत्या

मुंबई पुलिस नहीं दे रही सुरक्षाः नीरज सिंह बबलू

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर समय जैसे-जैसे बीतता जा रहा है यह मामला और भी उलझता जा रहा है। इस केस को लेकर ऐक्टर के परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी है और उनका कहना है कि इस मामले से जुड़े गवाहों को धमकाया जा रहा है और ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस बारे में बातें करते हुए सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू ने काफी कुछ कहा है। एएनआई के ट्वीट में बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने आरोप लगाया है कि सुशांत केस में गवाहों को धमकाया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुंबई पुलिस उन गवाहों को सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर रही। नीरज कुमार बबलू ने यह भी कहा है कि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में गवाहों की हत्या भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि गवाहों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए। बता दें कि सुशांत केस में रोज लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और मामला दिन-ब-दिन सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। इससे पहले भी नीरज कुमार बबलू ने आरोप लगाया था कि दिवंगत अभिनेता की डायरी से छेड़छाड़ की जा रही है। नीरज कुमार बबलू के अनुसार, सुशांत राजपूत हमेशा डायरी लिखा करते थे। उनकी मौत के बाद मुंबई पुलिस उनके सामने सारी डायरियां उठाकर ले गई थी। मुंबई पुलिस की तरफ से डायरी के साथ कुछ छेड़छाड़ भी की गई है, लेकिन डायरी में बचा हुआ जो कुछ भी पुलिस को मिला है, उसमें लोग देख सकते हैं कि सुशांत ने अपने भविष्य की पूरी प्लानिग कर रखी थी। दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मीडिया वालों से अनुरोध किया है कि इस केस की जांच से जुड़ी अहम जानकारियां वे बाहर न लाएं, क्योंकि इस वजह से मामले की जांच को खतरा हो सकता है और परिवार को न्याय मिलने में दिक्कत आ सकती है।

मल्लिका सिंह ने शेयर कीं 'गुलशन मामा' उर्फ सुशांत सिंह राजपूत संग क्यूट फोटोज

नई दिल्ली, एजेंसी। सुशांत सिंह राजपूत की भांजी मल्लिका सिंह एक्टर के काफी करीब थीं। किताबों से प्यार, डॉग लवर और पार्टनर इन क्राइम, जैसे सभी बॉन्ड्स एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले वीडियोज और फोटोज इसका सबूत हैं। दोनों जब भी साथ होते थे तो खुश होते थे। एक्टर की मौत के बाद मल्लिका सिंह लगातार पोस्ट शेयर कर रही हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक नजर मल्लिका और सुशांत के पोस्ट पर डालिए। आपके भी चेहेर पर मुस्कान आ जाएगी। आपको बता दें कि मल्लिका सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन की बेटी हैं। सुशांत केवल 14 साल के थे जब मल्लिका ने उनकी जिंदगी में कदम रखा। दोनों ही एक-दूसरे के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे। देखिए मल्लिका सिंह की फोटो, उनके गुलशन मामा के साथ। आपको बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। केस सीबीआई के हाथ में देने की डिमांड कर रहा है। एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति फैन्स को केस के बारे में अपडेट दे रही हैं। हाल ही में श्वेता ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला लेने की निवेदन करते हैं। हम सभी उनसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं और इत्मिनान से इंतजार कर रहे हैं। केस की सुनवाई में जितनी भी देर हो रही है, हर मिनट दर्द और दिल टूटने जैसा लग रहा है।

पंडित जसराज के निधन पर बॉलिवुड का छलका दर्द संगीत जगत के सितारे के खोने पर दुखी सिलेब्स

पद्म विभूषण पंडित जसराज ने अधिकांश शास्त्रीय गायन किया और सिर्फ 4 फिल्मों को अपने सुरों से सजाया। पंडित जसराज के निधन पर बॉलिवुड सिलेब्स ने शोक जताया है। भारतीय संगीत जगत के महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। अपने 80 साल के संगीत के सफर में उन्हें कई अवॉर्ड्स से नवाजा गया था। यहां तक कि पिछले साल एक ग्रह का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। पद्म विभूषण पंडित जसराज ने अधिकांश शास्त्रीय गायन किया और सिर्फ 4 फिल्मों को अपने सुरों से सजाया। इनमें 1966 में आई फिल्म लड़की सहयाद्री, 1975 में आई की फिल्म बीरबल माई ब्रदर, 2008 में आई फिल्म 1920 और 2012 में आई फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अपनी आवाज दी थी। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, महान शास्त्रीय गायक और मां सरस्वती के उपासक संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर मुझे असीम दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक

स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए प्रकाशन, मुद्रक व संपादक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।

संपादक- कंचन सोलंकी

TITLE CODE- UPHIN48974

Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।